वर्ष: 2 अंक: 13

1-15 जनवरी, 2022 (नि:शुल्क)

न्यू इंडिया समाचार

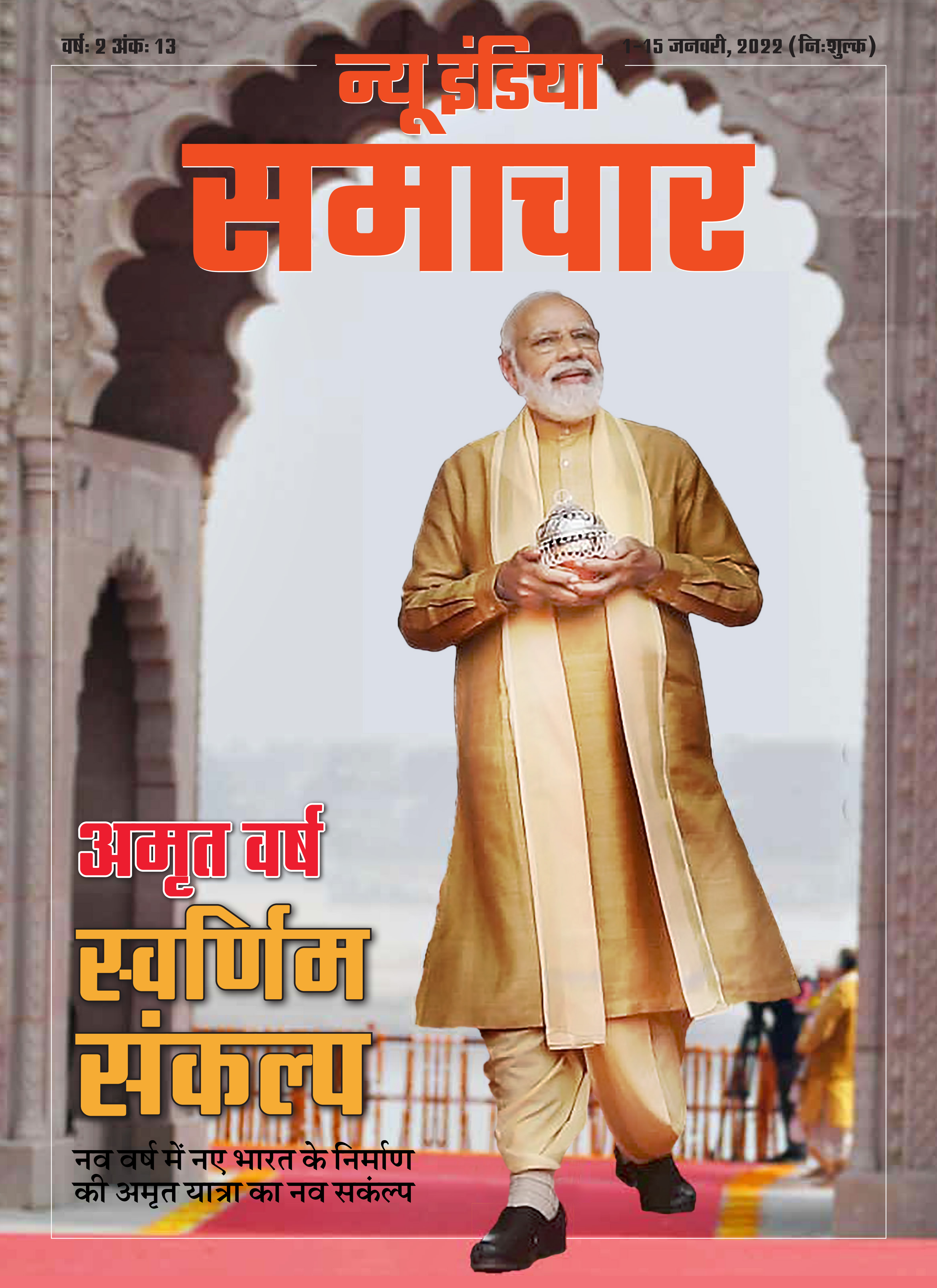

अमृत वर्ष

स्वर्णिम संकल्प

नव वर्ष में नए भारत के निर्माण
की अमृत यात्रा का नव संकल्प

VISIT…

LANZAROTE

Caliente.com

सेना दिवस
15 जनवरी

भारत की सेना...
मां भारती की आन-बान और शान

> "भारत के हर नागरिक को हमारी सेना पर अटूट विश्वास है, जो राष्ट्र की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहती है और इसके साथ ही ये भी नहीं भूला जा सकता कि जवान आपदा के समय लोगों को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं।"
>
> **नरेंद्र मोदी,** प्रधानमंत्री

न्यू इंडिया
समाचार
वर्ष: 02, अंक: 13 | 1-15 जनवरी, 2022

संपादक
जयदीप भटनागर,
प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

वरिष्ठ सलाहकार संपादक
संतोष कुमार

वरिष्ठ सहायक सलाहकार संपादक
विभोर शर्मा
सहायक सलाहकार संपादक
चन्दन कुमार चौधरी

भाषा संपादन
सुमित कुमार (अंग्रेजी), अनिल पटेल (गुजराती), नदीम अहमद (उर्दू), शोणित कुमार गोस्वामी (असमिया), विनया पी.एस. (मलयालम), पॉलमी रक्षित (बंगाली), हरिहर पंडा (ओड़िया)

सीनियर डिजाइनर
श्याम शंकर तिवारी
रविन्द्र कुमार शर्मा
डिजाइनर
दिव्या तलवार, अभय गुप्ता

प्रकाशक और मुद्रक:
सत्येन्द्र प्रकाश,
प्रधान महानिदेशक, बीओसी
(ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020

पत्राचार और ईमेल के लिए पता:
कमरा संख्या-278,
ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड
कम्युनिकेशन, सूचना भवन, द्वितीय
तल, नई दिल्ली- 110003
ईमेल- **response-nis@pib.gov.in**

आर. एन. आई. नंबर
DELHIN/2020/78812

अंदर के पन्नों पर...

नए भारत की नई भोर

आवरण कथा | आजादी की अमृत यात्रा के पहले नव वर्ष में पढ़िए कैसे संकल्प से सिद्धि के रास्ते नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहा है देश। पेज 14-30

बनारस की नई सुबह

काशी-विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन, 4 दशकों से लंबित सरयू नहर परियोजना की शुरुआत। पेज 06-10

जिनके अद्मय साहस से दुनिया का सबसे ऊंचा 'कायद पोस्ट' बना 'बाना' पोस्ट | पेज 04

श्रद्धांजलि: जनरल बिपिन रावत | पेज 05

प्रगति के पथ पर पूर्वांचल को मिल रही नई पहचान
गोरखपुर में एम्स सहित 3 परियोजनाओं की शुरुआत | पेज 11-13

कोविड काल की छाया से मुक्त हुई अर्थव्यवस्था
दूसरी तिमाही के आंकड़े रहे उत्साहजनक | पेज 31-32

'सबके लिए आवास' का सपना साकार
कैबिनेट के फैसले | पेज 33

दिल्ली से देवभूमि तक की दूरी अब ढाई घंटे में
दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर का शिलान्यास | पेज 34-35

हर घर टीके की दस्तक
कोविड से जंग में आगे बढ़ रहा है भारत | पेज 36-37

घर-घर उजाला से जीवन हो रहा रोशन
उजाला योजना से जीवन हो रहा सुगम | पेज 38-39

भारत-रूस संबंधों को मिला नया आयाम
कोविड के बीच रूस के राष्ट्रपति का केवल दूसरा विदेशी दौरा | पेज 44

जिन्होंने आजादी की जलाई अलख समाज के लिए छोड़ गए आदर्श
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस बार पढ़िए डॉ. सैफुद्दीन किचलू, महादेव भाई देसाई के साथ कुछ अन्य नायकों की कहानी। पेज 40-43

संपादक की कलम से...

सादर नमस्कार।

नववर्ष की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

वर्ष 2022, हर साल की भांति केवल कैलेंडर में बदलाव भर नहीं है। यह राष्ट्र की जीवन यात्रा का एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है- स्वतंत्र भारत का। देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है तो यह अवसर एक प्रतीक बन रहा है नए भारत का, कुछ उसी तरह जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चरखे और नमक को आजादी के आंदोलन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75वें वर्ष को एक ऐसा अवसर बना दिया है जो अपने स्वर्णिम काल यानी 2047 तक देश को एक बार फिर सोने की चिड़िया बनाने को संकल्पित है।

बीते कुछ वर्षों में राष्ट्र ने प्रगति का नया प्रतिमान कायम किया है। लेकिन अभी भी देश को मीलों का सफर तय करना है। विकास को हर क्षेत्र में कुछ लोगों की बजाए शत-प्रतिशत तक ले जाना है, जिसे साकार करने के लिए शुरू हो चुकी है- अमृत यात्रा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम को जन आंदोलन बनाना हो या फिर विकास की यात्रा में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों को समायोजित करना, लक्ष्य से कहीं आगे बढ़कर भारत ने मजबूत नींव तैयार कर दी है। अब अमृत काल में भारत का लक्ष्य विकास को टुकड़ों में बांटकर नहीं, यहां से वहां तक ही नहीं, बल्कि छूटे हुए समाज के सभी वर्ग, क्षेत्र, गांव-शहर, कोना-कोना को साथ लेकर चलने का रखा है, ताकि विकास सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी हो। जल-थल-नभ हर क्षेत्र में देश ने गति पकड़ी है। बीते कुछ वर्षों के प्रयास ने सिद्ध किया है कि 21वीं सदी का भारत बड़े लक्ष्य गढ़ने और उसे साकार करने का सामर्थ्य रखता है। इस नववर्ष विशेषांक में अमृत वर्ष तक का भारत कैसा है और स्वर्णिम वर्ष का भारत कैसा होगा, इस पूरी अमृत यात्रा को आवरण कथा बनाया गया है।

व्यक्तित्व के रूप में परमवीर नायब सूबेदार बाना सिंह के शौर्य की कहानी, अमृत महोत्सव की कड़ी में महानायकों की प्रेरक गाथा, भारत की आर्थिक प्रगति, दिव्यता-भव्यता की मिसाल काशी कॉरिडोर, देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे से लेकर पूर्वांचल की प्रगति और कोविड में 55 फीसदी से अधिक पात्र आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने जैसे विषय इस अंक में शामिल हैं।

कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहिए। अपना सुझाव आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं:

पता- कमरा संख्या- 278, द्वितीय तल,
ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,
सूचना भवन, द्वितीय तल
नई दिल्ली- 110003
ईमेल- **response-nis@pib.gov.in**

जयदीप भटनागर

(जयदीप भटनागर)

"भारत के एक्शन और विजन पर पूरी दुनिया में उत्साह है, हमने सभी विकासशील देशों के विषयों को पुरजोर ढंग से उठाया है"
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से विशेष बातचीत। पढ़ें पेज: 30 से 33 पर
वर्ष: 2 अंक: 11
1-15 दिसंबर, 2021 (निःशुल्क)
न्यू इंडिया
समाचार
#COP26
मानवता बचाने को भारत बना अग्रदूत
पर्यावरण बचाने को 'पंचामृत' के संकल्प के साथ ग्लासगो में भारत ने दिखाई दुनिया को राह

आपकी बात...

मैं 'न्यू इंडिया समाचार' पत्रिका के शुरुआती अंकों से ही प्रशंसक रहा हूं। मुझे अगले अंक का बेताबी से इंतजार रहता है। पत्रिका मे सभी सरकारी कार्य योजनाओं, गतिविधियों की जानकारियां बहुत ही सुलभ और सहज भाषा में दी जाती है। हर बार की तरह इस बार की आवरण कथा 'ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया बचाने को भारत बना अग्रदूत' के साथ ही अन्य पन्नों पर दी गई हर एक सामग्री बेहतरीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाबा केदार की नगरी के कायाकल्प की परिकल्पना को साकार होने की जानकारी ने घर बैठे बाबा केदार के दर्शन करवा दिए।

नरेश कानूनगो
kanungo.naresh@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका बहुत बेहतर है। मैं नियमित पत्रिका का अध्ययन करता हूं। मुझे यह अब तक की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका लगी है। सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी, देश दुनिया की जानकारी एवं देश में नया क्या हो रहा है, इन सब की जानकारी यह पत्रिका देती है। बेहतरीन संपादन के लिए ढेरों शुभकामनाएं।

-मुकेश कुमार ऋषि वर्मा
mukesh123idea@gmail.com

अपने सुझाव हमें भेजें

पत्राचार और ईमेल के लिए पता:

कमरा संख्या-278,
ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन
सूचना भवन, द्वितीय तल
नई दिल्ली- 110003

ईमेल- response-nis@pib.gov.in

मैं शहरी क्षेत्र में रहता हूं जहां सोशल मीडिया का काफी प्रचलन है। हालांकि सोशल मीडिया पर वास्तविक जानकारी नहीं रहती है। ऐसे में देश व देशवासियों के हित में सरकार द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण विकास कार्यों का कई बार पता ही नहीं चलता। न्यू इंडिया समाचार पत्रिका आम जन को उन सब से अवगत कराने व विकास के कार्यों की वास्तविक स्थिति बताने का एक अच्छा और विश्वसनीय माध्यम बन रही है।

-सतीश त्यागी काकड़ा
tyagisk67@gmail.com

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का 1 से 15 दिसंबर 2021 का अंक ई-मेल के जरिए प्राप्त हुआ। इस बार के अंक में बेहतरीन समाचार पढ़ने को मिला। अंक में गोवा में संपन्न हुआ 52वां फिल्म महोत्सव और डॉ. राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, डॉ. आंबेडकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक्सप्रेस वे एवं कोविड-19 पर उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त हुई। पत्रिका का आवरण बेहतरीन है। आशा है ऐसी पत्रिकाएं भविष्य में भी हमको पढ़ने को मिलती रहेंगी।

shrigopal6@gmail.com

मैं न्यू इंडिया समाचार पत्रिका ऑनलाइन पढ़ता हूं। इस पत्रिका में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत अच्छी जानकारी पढ़ने को मिलती है। इस पत्रिका को पढ़ने से मेरी विश्लेषणात्मक क्षमता व गहरी समझ विकसित हो रही है।

-हनवंत सिंह राठौड़
hanwantsinghrathore0@gmail.com

जिनके अदम्य साहस से दुनिया का सबसे ऊंचा 'कायद पोस्ट' बना 'बाना' पोस्ट

जन्म: 6 जनवरी 1949

बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। दूर-दूर तक सफेद बर्फ से ढकी वह जगह धरती से 21 हजार फीट ऊंचा था। यहां से दुश्मन की फौज भारतीय सेना के सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों और हर कदम पर नजर रख सकती थी। एक छोटा, लेकिन अजेय दुर्ग- कायद पोस्ट। जिसके दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें, जिन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। जिसका काम था- कायद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था, ये जानते हुए भी नायब सूबेदार बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं आगे बढ़ाया। वे इस कार्यवाहक दल में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई।

सियाचिन की भयंकर जलवायु के साथ तीव्र बर्फीले तूफान, माइनस 40 डिग्री के लगभग तापमान और ऑक्सीजन की कमी जीवित रहने के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। लेकिन नायब सूबेदार बाना सिंह और उनके जवानों ने शून्य दृश्यता की स्थितियों में जोखिमपूर्ण मार्ग से बर्फ की 457 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ाई की। भयंकर तूफानी रात, अभी एक तिहाई राह पार किया था कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। इससे विचलित होना, पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीली कील वाले बूट पहनकर रस्सियों और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। सुबह सबेरे कोई पांच बजे का समय था। बाना सिंह साथियों के साथ आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे थे, जहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े और हथगोले फेंककर दुश्मन के बंकर को ध्वस्त कर दिया। बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर। स्टेनगन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोंपते तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वे कहर बरपा रहे थे। कुछ पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और जो बचा उसने डर कर चोटी से छलांग लगा ली। आखिरकार बाना सिंह ने वहां से दुश्मनों का सफाया कर दिया और कायद पोस्ट वापस भारतीय सेना के कब्जे में आ गई।

जब पीएम बनने के बाद पहली दिवाली पर ही सियाचिन पहुंचे नरेंद्र मोदी

सियाचिन स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे नायक वैसे ही रहते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओ में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर-दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य। निर्जनता का सन्नाटा। इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी-अपनी चौकियों की चौकसी करते हैं भारतीय सैनिक। सफेद बर्फ से भरी भूमि का नाम सियाचिन है जिसका मतलब है- गुलाबों का संग्रह। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली दिवाली सियाचिन में ही जवानों के साथ मनाई थी। तब उन्होंने कहा था, "जब तक कोई इन बर्फीले ग्लेशियर को नहीं देखेगा, माइनस 30-40 डिग्री में जवान कैसे तैनात होते हैं, इसे देखेगा नहीं, उसे कल्पना नहीं आ सकती है कि हमारे फौज, हमारे जवान कितनी कठिनाइयों के बीच, कितने दुर्गम इलाकों के बीच, मातृभूमि की रक्षा के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं।"

भारत के परमवीर बाना सिंह की फौज में आने की कहानी भी दिलचस्प है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेती-बाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से काफी प्रभावित थे। ऐसा इसलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। वह चाहते थे कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे। जब कभी बाना सिंह छुट्टी पर आए सैनिकों से मिलते या देखते तो बहुत खुश होते और कहते थे- मेरे को भी ये वर्दी अच्छी लगती है, मैं भी पहनूंगा और देश की सेवा करूंगा। बाना सिंह की ये इच्छा 20वें साल ठीक उनके जन्मदिन पर ही पूरी हुई। जन्मदिन पर उन्हें शायद इससे बेहतर तोहफा नहीं मिल सकता था क्योंकि 6 जनवरी 1969 को वे भारतीय सेना में भर्ती हुए। ●

श्रद्धांजलि: जनरल बिपिन रावत

हिंद के नायक

बाकया 1977-78 का है। एनडीए की लिखित परीक्षा पास कर एक नौजवान इंटरव्यू के लिए ब्रिगेडियर के सामने पहुंचा। इस नौजवान को ट्रैकिंग का बहुत शौक था। इंटरव्यू में ब्रिगेडियर ने सवाल किया- अगर आपको 4-5 दिन के लिए ट्रैकिंग पर जाना हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज बताइए, जिसे आप अपने पास रखना चाहेंगे। नौजवान ने कहा- माचिस। ब्रिगेडियर ने कई अन्य सामान रखने का जवाब चुनने के लिए दबाव बनाया, लेकिन उसने अपना निर्णय नहीं बदला। यह नौजवान थे, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने वाले जनरल बिपिन रावत। निर्णय लेना और उस पर अडिग रहना, जिनकी पहचान रही। चाहे म्यांमार की सीमा के पार जाकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारना हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए आतंक को जवाब देना...भारत के हर एक सैन्य ऑपरेशन में उनकी अहम भूमिका रही है।

बात 1993 की है। बिपिन रावत 5/11 गोरखा राइफल्स में मेजर के पद पर तैनात थे। कश्मीर के उरी इलाके में वो अपने कुछ जवानों के साथ गश्त कर रहे थे। उसी दौरान पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी। बिपिन रावत भी उस गोलीबारी की जद में आ गए। एक गोली उनके टखने पर लगी और वो चूर हो गया। एक छर्रा उनके दाहिने हाथ पर लगा। आनन-फानन उन्हें श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका हाथ और टखना तो ठीक कर दिया, लेकिन रावत को डर था कि गोली लगने के बाद उन्हें सीनियर कमांड कोर्स में शामिल होने से रोक न दिया जाए। उन्होंने हार नहीं मानी। बैसाखी के सहारे चलना शुरू किया और एक महीने में ही रिकवर हो गए। 2015 में बिपिन रावत लेफ्टिनेंट जनरल थे। उनके ऊपर नागालैंड के दीमापुर स्थित 3 कॉर्प्स हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी थी। 3 फरवरी 2015 को सुबह 9.30 बजे बिपिन रावत, एक कर्नल और दो पायलट के साथ चीता हेलिकॉप्टर पर सवार हुए। दीमापुर से उड़ान भरने के बाद हेलिकॉप्टर जमीन से 20 फीट ऊपर गया, तभी इंजन फेल हो गया। कुछ सेकेंड में ही वो जमीन पर आ गिरा। उसमें सवार सभी लोगों को चोट आई, लेकिन एक बार फिर बिपिन रावत ने मौत को मात दे दी।

यह वो दो किस्से हैं, जब अपनी जाबांजी से उन्होंने मौत को मात दी। लेकिन 8 दिसंबर को होनी को कुछ और ही मंजूर दिया। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलिकॉप्टर क्रैश में देश के पहली सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोगों का देहांत हो गया। जनरल रावत के योगदान को याद करते हुए 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारतप्रेमी के लिए, हर राष्ट्रभक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबांज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है।"●

सीडीएस जनरल बिपिन रावत (1958-2021)

वो ऑपरेशन जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा...

- बात जून 2015 की है। मणिपुर में हमारी सेना पर आतंकी हमला हुआ। 18 सैनिकों की शहादत से देश में उबाल था। उस दौर में संयोग से 21 पैरा थर्ड कॉर्प्स के कमांडर बिपिन रावत ही थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत पर आंच आती है तो क्या होता है। इस यूनिट के पैरा कमांडो ने सरहद पार करके म्यांमार में ऑपरेशन किया औरआतंकी ग्रुप के 60 से ज्यादा आतंकियों को सीमा पार जाकर ढेर कर दिया।
- पाकिस्तान की हरकतों का जवाब उन्होंने अपने अंदाज में दिया। 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय सेना की स्पेशल कमांडो यूनिट ने रातों-रात ऑपरेशन किया। कई आतंकियों के साथ पाकिस्तान के सैनिक भी ढेर कर दिए। यह हमारे उरी और सीआरपीएफ कैम्प पर हुए हमला का जवाब था।

> **“ जनरल बिपिन रावत एक बेमिसाल सैनिक और सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाई। सामरिक और रणनीतिक मामलों में उनकी दृष्टिकोण अतुलनीय था। उनके नहीं रहने से मैं बहुत दुखी हूं। भारत उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। ”**
>
> **- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

43 साल बनाम 33 माह

बनारस की नई सुबह

काशी-विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकापर्ण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

बुनियादी ढांचा हो या फिर देश के सांस्कृतिक गौरव को नया और आधुनिकतम स्वरूप देने की पहल, केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। वर्षों से लटके हुए प्रोजेक्ट जहां 2014 के बाद धरातल पर साकार हो रहे हैं तो सांस्कृतिक धरोहरों को भी भव्यतम रूप देकर नई गौरवगाथा लिखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के दो उदाहरणों से आप इसे समझ सकते हैं। एक- सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट, जिसकी नींव तो रखी गई थी 1978 में लेकिन असल में काम की शुरुआत यहां 2017 में हो पाई। दूसरा- काशी विश्वनाथ कॉरीडोर, जिसकी नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को रखी थी और मात्र 33 माह 4 दिन में ही इस प्रोजेक्ट के पहले चरण को पूरा कर दिया गया। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया तो 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात देकर यह बता दिया कि उनकी सरकार में अब काम न तो अटकते हैं और न लटकते हैं...

एक समय था, जब वाराणसी में बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर कहा जाता था कि इस शहर का कुछ नहीं हो सकता। उसके कारण भी थे, कदम-कदम पर मुश्किलें। कहीं रास्ते में मंदिर तो कहीं अतिक्रमण। कहते हैं कि यहां बुनियादी संरचना का हाल मधुमक्खी के छत्ते जैसा था, जिसे कोई छेड़ना नहीं चाहता था। उस पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ही इस कदर अतिक्रमण था कि ढंग से चलना भी कभी-कभी मुश्किल हो जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जरिए वाराणसी की इस परिभाषा को बदल दिया है। 13 दिसंबर को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभ रेवती नक्षत्र में उद्घाटन करते हुए वारणसी से उनका प्रेम भावों में झलका तो शब्दों ने हृदय के भीतर के उस विस्तार को जगह दी, जिसका सपना 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था। उन्होंने कहा, “शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई शुभ अवसर होता है तो सारी दैवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चैतन्य ब्रम्हांड इससे जुड़ा है। वैसे अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने। जहां तक मानवीय दृष्टि जाती है। विश्वनाथ धाम को समय पर पूरा करने से पूरा विश्व जुड़ा है। आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। विक्रम संवत 2078, दशमी तिथि एक नया इतिहास रच रही है।”

प्रधानमंत्री ने काशी आध्यात्मिकता का जिक्र किया तो महान विरासत के साथ आजादी के अमृत वर्ष में विकास यात्रा का अपना संकल्प भी दोहराया। प्रधानमंत्री के संबोधन के अंश

काशी की आध्यात्मिकता को नमन

हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा हमारी अंतर-आत्मा को जागृत कर देती है।

> “
> काशी शब्दों का विषय नहीं है,
> संवेदनाओं की सृष्टि है।
> काशी वो है- जहां जागृति ही जीवन है!
> काशी वो है- जहां मृत्यु भी मंगल है!
> काशी वो है- जहां सत्य ही संस्कार है!
> काशी वो है- जहां प्रेम ही परंपरा है!
>
> – **नरेंद्र मोदी**, प्रधानमंत्री

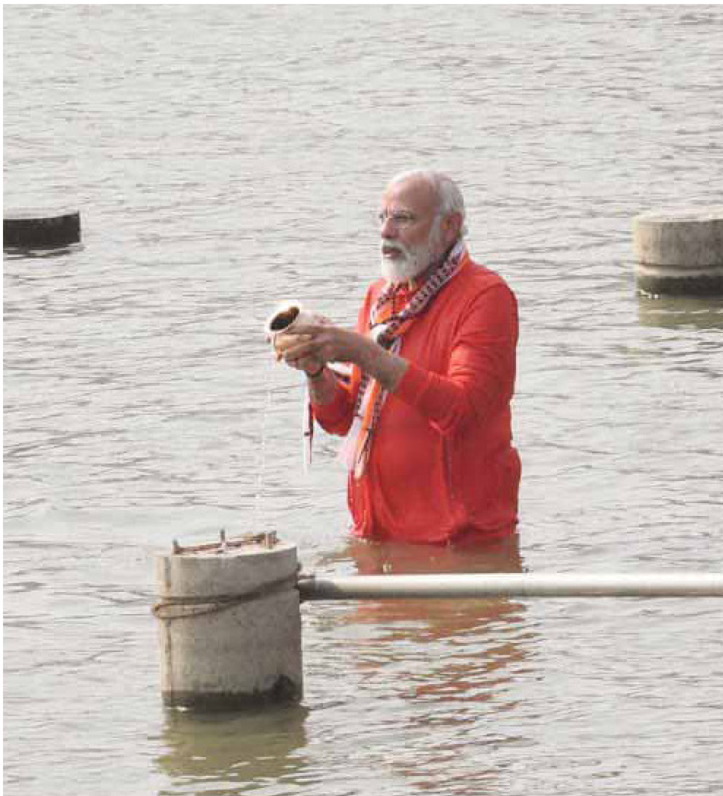

सनातन परंपरा का जिक्र

विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है, हमारे भारत की सनातन संस्कृति का! ये प्रतीक है, हमारी आध्यात्मिक आत्मा का! ये प्रतीक है, भारत की प्राचीनता का, परम्पराओं का! भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का।

परंपरा और आधुनिकता के संगम पर जोर

विश्वनाथ धाम के नए परिसर से पहले जो मंदिर क्षेत्र केवल तीन हजार वर्ग फीट में था, वो अब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50 से 75 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी पहले मां गंगा का दर्शन-स्नान, और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम।

उज्ज्वल भविष्य की नींव

काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये

श्रमिकों का सम्मान

मैं आज अपने हर उस श्रमिक भाई-बहन का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है। कोरोना के विपरीत काल में भी, उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया।

प्रधानमंत्री मोदी अचानक कॉरिडोर बनाने वाले श्रमिकों से मिलने पहुंच गए। सभी नए परिसर की सीढ़ियों पर बैठे थे। प्रधानमंत्री वहां पहुंचे और करीब 10 मिनट तक उन पर फूल बरसाते रहे। उनके साथ सीढ़ी पर ही बैठ गए। उन्होंने मजदूरों से विश्वनाथ धाम के निर्माण से जुड़े उनके अनुभव पूछे। इसके बाद उन्होंने बाबा का जयकारा लगाते हुए सभी के साथ फोटो खिंचवाई।

श्रद्धालुओं को नई सुविधाएं

- काशी विश्वनाथ का मंदिर अब गंगा से सीधे जुड़ गया है। श्रद्धालु जलासेन घाट, मणिकर्णिका और ललिता घाट पर गंगा स्नान कर सीधे बाबा धाम में प्रवेश कर सकेंगे।
- विशालकाय बाबा धाम के 3 यात्री सुविधा केंद्रों में श्रद्धालुओं को अपना सामान सुरक्षित रखने, बैठने और आराम की सुविधा मिलेगी।
- कला और संस्कृति की नगरी काशी में कलाकारों के लिए एक और सांस्कृतिक केंद्र की सौगात मिलेगी। दो मंजिला इमारत सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए है।
- विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए योग और ध्यान केंद्र के रूप में वैदिक केंद्र को स्थापित किया गया है। धाम क्षेत्र में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पिरिचुअल बुक सेंटर धार्मिक पुस्तकों का नया केंद्र होगा।
- श्रद्धालुओं के लिए बाबा की भोगशाला भी स्थापित की गई है। यहां एक साथ 150 श्रद्धालु बैठकर बाबा विश्वनाथ का प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे।
- सनातन धर्म में काशी में मोक्ष की मान्यता है। विश्वनाथ धाम में मुमुक्षु भवन बनाया गया है। इससे लगभग 100 कदम की दूरी पर महाश्मशान मणिकर्णिका है।
- विश्वनाथ धाम में प्रवेश के लिए 4 विशालकाय द्वार बनाए गए हैं। पहले यहां सिर्फ संकरी गलियां थीं। सुरक्षा के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है।
- धाम में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा से लेकर एंबुलेंस तक की व्यवस्था रहेगी। एक जिला-एक उत्पाद और हस्तशिल्प के सामान की दुकानें और फूड कोर्ट भी बनाए गए हैं।
- महादेव के प्रिय रुद्राक्ष, बेल, पारिजात के पौधों के साथ ही अशोक के पेड़ और तरह-तरह के फूल धाम परिसर में लगाए जा रहे हैं।
- धाम में दिव्यांगों और बुजुर्गों के आवागमन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रैंप और एस्कलेटर की अत्याधुनिक सुविधा धाम में उपलब्ध है।

लगभग 244 साल बाद हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार

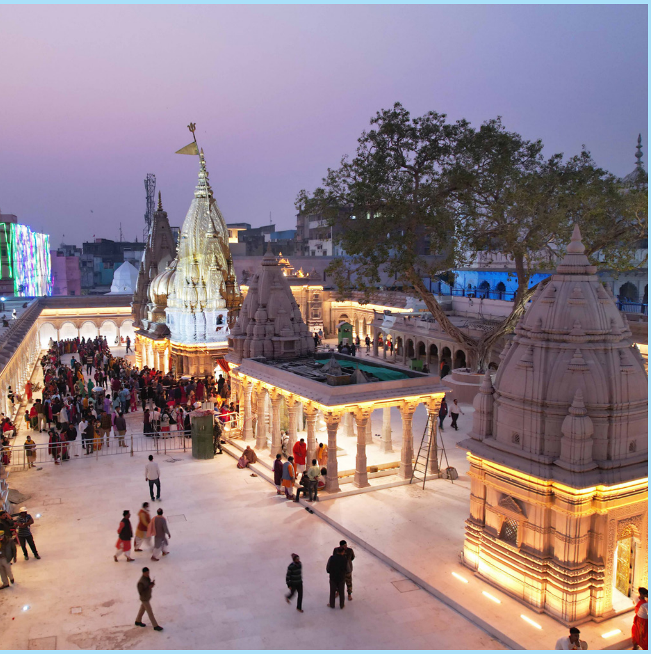

- काशी विश्वनाथ मंदिर पर वर्ष 1194 से लेकर 1669 तक कई बार हमले हुए। 1777 से 1780 के बीच महारानी अहिल्याबाई होलकर ने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था।
- उसके बाद 54 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले काशी विश्वनाथ धाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2019 को किया था।
- प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए 5 लाख 27 हजार वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्रफल में इसे विकसित किया गया है। 339 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सहूलियतों का खास ध्यान रखा गया है।
- पहले तंग गलियों में स्थित जिस विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, वहां अब 2 लाख श्रद्धालु खड़े होकर दर्शन-पूजन कर सकेंगे।

प्रोजेक्ट के लिए 300 से ज्यादा इमारतों को खरीदा गया

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर का क्षेत्रफल पहले 3,000 वर्ग फीट था। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर के आसपास की 300 से ज्यादा बिल्डिंग को खरीदा गया। इसके बाद 5 लाख वर्ग फीट से ज्यादा जमीन में लगभग 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्माण किया गया। धाम के लिए खरीदे गए भवनों को नष्ट करने के दौरान 40 से अधिक मंदिर मिले। उन्हें भी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट के तहत नए सिरे से संरक्षित किया गया है।

परिसर, साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं।

विरासत को सहेजने की प्रतिबद्धता

आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को फिर से संजो रहा है। यहां काशी में तो माता अन्नपूर्णा खुद विराजती हैं। मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा, एक शताब्दी के इंतजार के बाद अब फिर से काशी में स्थापित की जा चुकी है।

भारतवासियों के लिए संकल्प

मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए तीन संकल्प चाहता हूं- स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास।

43 साल बाद सरयू नहर परियोजना का शुभारंभ

सरयू नहर परियोजना की मुख्य नहरें

सरयू मुख्य नहर	63 किमी
सरयू लिंक नहर	43 किमी
राप्ती मुख्य नहर	125 किमी
राप्ती लिंक नहर	21 किमी

उत्तर प्रदेश की सरयू नहर परियोजना का काम 1978 में बहराइचपुर से शुरू किया गया था। लेकिन लेटलतीफी का शिकार इस परियोजना का काम 2017 तक मात्र 52% तक ही पूरा हो पाया। लेकिन देशभर में लंबे समय से अटके हुए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर तेजी से काम शुरू किया गया तो इस परियोजना का बाकी का 48 फीसदी काम मात्र साढ़े चार साल में पूरा कर लिया गया। 11 दिसंबर को बलरामपुर में इसकी शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था, तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज ये लगभग 10 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। पहले ही सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत देश को चुकानी पड़ी है। सरकारी पैसा है तो मुझे क्या, ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई थी। इसी सोच ने सरयू नहर परियोजना को लटकाया भी, भटकाया भी।"

9 जिलों के 29 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा

- 6 हजार 623 किलोमीटर नहरों का जाल बिछाया गया। ये सभी नहरें गांवों से कनेक्ट कर दी गई हैं। पूर्वांचल के 9 जिलों की पांच नदियों को जोड़ती हैं।
- घाघरा से सरयू, सरयू से राप्ती, राप्ती को बाणगंगा और बाणगंगा से रोहिणी नदी को जोड़ा गया। पांचों नदियों से पानी लेकर सिंचाई के लिए नहर में छोड़ा जाएगा। 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया।
- नहर का पहला छोर घाघरा और सरयू नदी पर बने बहराइच के सरयू बैराज पर है।
- बहराइच, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, गोरखपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर और महराजगंज के 6,200 गांवों के 29 लाख से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
- इस परियोजना से 14 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई हो सकेगी। परियोजना की लंबाई 318 किलोमीटर है, जबकि 6 हजार 590 किलोमीटर में इसके लिंकेज हैं।

प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

पूर्वांचल के विकास पर विशेष फोकस

- **20 अक्टूबर**– कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआत। बौद्ध सर्किट को बढ़ावा के साथ पूर्वांचल के विकास को इससे नई गति मिली।
- **25 अक्टूबर**- सिद्धार्थनगर सहित 9 नए मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण। इससे पूर्वांचल के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना होगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत।
- **16 नवंबर**– पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश का दूसरा एक्सप्रेस वे नए रोजगार के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की सीढ़ी बनेगा।
- **7 दिसंबर**- गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने की शुरुआत। गंभीर बीमार लोगों को दिल्ली या लखनऊ भागने से निजात मिलेगी तो खाद कारखाने से किसानों को मिलेगी नई ऊर्जा।
- **11 दिसंबर**– सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण। 9 जिलों के 29 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा इसका सीधा लाभ।
- **13 दिसंबर**– वाराणसी में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी-विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया। ●

प्रगति के पथ पर पूर्वांचल को मिल रही नई पहचान

जिसका हम शिलान्यास करते हैं, उसका उद्घाटन भी हमीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस शब्द को यथार्थ में परिवर्तित होते हुए देश निरंतर देख रहा है। अब इसी कड़ी में 7 दिसंबर को गोरखपुर में एम्स, खाद कारखाना और आईसीएमआर के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन की जिन तीन परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसमें से दो की आधारशिला भी 22 जुलाई 2016 को उन्होंने ही रखी थी। विकास के नए आयामों में एक्सप्रेस-वे के बाद अब खाद कारखाने और स्वास्थ्य ढांचे की सौगात से पूर्वांचल की प्रगति को मिले नए पंख...

आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में उन्नत उत्तर प्रदेश बड़ा सहभागी है, जहां केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय से वे सभी क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं जो दशकों से राजनीतिक अनदेखी की वजह से मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेल रहा था। लेकिन पूर्वांचल में एक्सप्रेस-वे के निर्माण के पखवाड़े भर बाद ही गोरखपुर में तीन दशक से बंद पड़े खाद कारखाने की शुरुआत और एम्स जैसे अस्पताल से इस क्षेत्र के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के विकास को भी नई गति मिलने वाली है।

पूर्वांचल जो कभी सुविधाओं से वंचित था और कई गंभीर बीमारियों के भी अभिशाप से भी ग्रस्त था। ऐसी ही एक बीमारी जिसे जापानी एंसेफलाइटिस जिसे जापानी या दिमागी बुखार भी कहा जाता है, यह पूर्वांचल के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 2014 से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नए-नए कदमों की शुरुआत की। स्वच्छता को आंदोलन बनाया तो आयुष्मान भारत से आम जन को जोड़ते हुए 5 लाख रुपये तक की मुफ्त इलाज की सुविधा दी। शुद्ध पेयजल के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की और हर घर शौचालय के निर्माण से स्वच्छता को सुनिश्चित किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचारी रोगों के खिलाफ अभियान और हर घर दस्तक अभियान चलाया गया। इसके सार्थक परिणाम आए और पूर्वांचल जैसे इलाकों में जापानी बुखार के मामलों में कमी आई। केंद्र और राज्य के समन्वय से पूर्वांचल के साथ पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश अब जापानी बुखार के प्रकोप से बाहर निकल आया है। इससे होने वाली मृत्यु दर में 95%तक की कमी आई है। उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य हिस्सों में स्वस्थ भारत, सुरक्षित भारत के संकल्प के साथ आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूती मिल रही है।

प्रधानमंत्री का
संबोधन सुनने के लिए
QR कोड स्कैन करें।

गोरखपुर एम्स: चिकित्सा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, GORAKHPUR

स्वास्थ्य की रक्षा सर्वोपरि। बदहाल स्वास्थ्य ढांचे में सुधार लाने के लिए 2014 के बाद तेजी से काम किए हुए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की राह पर है। देश में नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, विश्वस्तरीय चिकित्सा तकनीकों को अपनाया, नई स्वास्थ्य नीति और ई-हेल्थ जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। पिछले सात वर्षों में 16 नए एम्स पर काम शुरू हुआ है। साथ ही, फिट इंडिया, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, आयुष्मान भारत, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जैसी मुहिम शुरू की गई। अकेले उत्तर प्रदेश को दो एम्स की सौगात मिली है। पहले प्रदेश के लोगों को इलाज के दिल्ली के एम्स में जाना पड़ता था। लेकिन अब वह एम्स गोरखपुर में आ गया है। जिससे पूर्वांचल के साथ पड़ोसी राज्य बिहार-झारखंड सहित पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं सहजता से मिल सकेगी।

पूर्वांचल को एम्स की सौगात से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

- 1000 करोड़ रुपये की लागत से 112 एकड़ में निर्मित गोरखपुर एम्स से गुणवत्तापूर्ण तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी।
- इसमें 750 बिस्तरों वाला अस्पताल, 18 स्पेशियलिटी, 17 सुपर स्पेशियलिटी विभाग और 14 ऑपरेशन थियेटर हैं। आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज का निर्माण।
- सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड की सुविधा सहित कई गंभीर बीमारियों का इलाज उपलब्ध होगा।
- चिकित्सा शिक्षा के 25 से अधिक पाठ्यक्रमों सहित एमबीबीएस की 125 सीटें हैं। इसके निर्माण से युवाओं को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आवागमन बढ़ने से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसका 5 साल के भीतर पूरा हुआ निर्माण कार्य।

आईसीएमआर क्षेत्रीय केंद्र से शोध में मदद

- नए भवन में अत्याधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था। संचारी और गैर संचारी रोगों में अनुसंधान के नए द्वार खुलेंगे।
- क्षेत्र के अन्य चिकित्सा संस्थानों को सहायता प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में जापानी इंसेफलाइटिस, एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम से निपटने में मदद मिलेगी।

> **“किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए, बहुत आवश्यक है कि उसकी स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती हों, सर्व सुलभ हों, सबकी पहुंच में हों। वर्ना मैंने भी इलाज के लिए लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक चक्कर लगाते, अपनी जमीन गिरवी रखते, दूसरों से उधारी लेते बहुत देखा है। मैं देश के हर गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए जी-जान से जुटा हूं।**
>
> **– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

आईसीएमआर: क्षेत्रीय केंद्र से शोध-अनुसंधान को बढ़ावा

कोविड महामारी ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लक्ष्य को बेहतर बनाया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नए-नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए नए-नए संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है। इसी दिशा में आईसीएमआर क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र गोरखपुर एक मिसाल है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र का नया भवन इलाके में मलेरिया, टीबी, एचआइवी, कैंसर और कुष्ठ रोगों पर अनुसंधान के नए क्षितिज खोलेगा। ये संस्थान नए और उभरते संक्रमणों, पोषण संबंधी समस्या और इसके अलावा शुगर, हाई बीपी जैसे रोगों को दूर करेगा। इससे अत्याधुनिक जांच की सुविधा का लाभ मिलेगा और सैंपल बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। ये संस्थान क्षेत्रीय स्तर की बीमारियों की जांच और इलाज के नए तरीकों की खोज करेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती देने के लिए बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के क्षेत्रीय शोध संस्थान गोरखपुर में 9 अत्याधुनिक लैब का लोकार्पण किया गया, जहां जापानी बुखार समेत विभिन्न कीटाणुओं-विषाणु जनित बीमारियों का परीक्षण और शोध कार्य किया जाएगा। सैंपल की जांच के लिए बड़े शहरों में नहीं भेजना होगा और इलाज तत्काल हो सकेगा। इससे पूर्वांचल के जिलों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। इस भवन का रिकॉर्ड गति से निर्माण किया गया है ताकि लोग इसका लाभ जल्द उठा सके।

अपना यूरिया / गोरखपुर खाद कारखाना आत्मनिर्भर कृषि का आधार

करीब 30 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े पूर्वांचल स्थित गोरखपुर खाद कारखाने का जीर्णोद्धार कर केवल 5 साल में ही शुरू कर सरकार ने मिसाल पेश की है, ताकि 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों की भी समृद्धि हो सुनिश्चित और यूरिया के क्षेत्र में भारत बने आत्मनिर्भर

अन्नदाता जिनका कठोर परिश्रम है देश का गौरव। कृषि विकास और किसान कल्याण को केंद्र सरकार की नीतियों और कामकाज में सदैव सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। बीते वर्षों में सरकार ने बीज, बीमा, बाजार और बचत पर चौतरफा काम किया है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, नीम कोटेड यूरिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचाई, खाद सब्सिडी में वृद्धि जैसे विभिन्न कदमों से किसानों की समृद्धि को सुनिश्चित किया गया है। देश में छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है। पैदावार और किसानों की आय बढ़ाने में देश की आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बंद पड़े खाद कारखानों के जीर्णोद्धार और क्षमता में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया। इसी कड़ी में 2016 में देश के पूर्वी राज्यों में वर्षों से बंद पड़े तीन खाद कारखानों (गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी) को फिर से शुरू करने के लक्ष्य के साथ हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (**HURL**) शुरू करने का एक बड़ा निर्णय लिया गया। इसी में शामिल था गोरखपुर खाद कारखाना जो 30 वर्षों से ठप पड़ा था। बंद पड़े कारखानों की वजह से किसान लंबे समय से परेशान थे तो बहुतों की नौकरियां छिन गई। कारखानों के कारण चलने वाले अन्य कारोबार भी सिमटते चले गए। इससे एक बड़ी आबादी के रोजी-रोजगार पर संकट आ गया था। खाद की आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित थी, जिसका फायदा बिचौलिए उठाते थे। यूरिया की जमाखोरी और कालाबाजारी होती थी। अधिक दाम पर खाद खरीदने के कारण किसानों पर आर्थिक मार पड़ती थी। यहां पर बनने वाले यूरिया को अपना यूरिया नाम दिया गया है। गोरखपुर में खाद कारखाने को फिर से शुरू कराने की लोगों की मांग पर पूर्व की सरकारों के वायदे सिर्फ खोखले ही साबित हुए। इस निराशा भरे माहौल को बदलने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खाद कारखाने के पुनरुद्धार की आधारशिला रखी। अब गोरखपुर की धरती का वह सपना साकार हुआ है। ●

गोरखपुर में एक खाद कारखाना, विकास की अनेक राह

- पूर्वांचल के किसानों की आकांक्षाओं को साकार करने और यूरिया की मांग-आपूर्ति की खाई को दूर कर किसानों को आसानी से रसायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- लगभग 8600 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित कारखाने से यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। कारखाने के साथ-साथ अन्य को मिलाकर 20 हजार रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
- कौशल प्रशिक्षण के जरिए लोगों को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। स्थानीय पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। यूरिया के आयात में कमी से विदेशी मुद्रा में बचत होगी। पश्चिमी-मध्य क्षेत्रों से यूरिया के कम परिवहन के कारण रेल और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव में कमी आएगी।

30 वर्षों से अधिक समय से बंद संयंत्र के शुरू होने से क्षेत्र में समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

3850
मीट्रिक टन यूरिया का प्रतिदिन उत्पादन होगा।

2200
मीट्रिक टन लिक्विड अमोनिया का उत्पादन होगा।

नए भारत की नई भोर

> अमृत काल 25 वर्ष का है। लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये इतना लंबा इंतजार भी नहीं करना है। हमें अभी से जुट जाना है। हमारे पास गंवाने के लिये एक पल भी नहीं है। यही समय है, सही समय है। हमारे देश को भी बदलना होगा और हमें एक नागरिक के नाते अपने आपको भी बदलना ही होगा। बदलते हुए युग के अनुकूल हमें भी अपने आपको ढालना होगा।
>
> – **नरेंद्र मोदी**, प्रधानमंत्री

आजादी के अमृत महोत्सव (75वीं वर्षगांठ) में प्रवेश के बाद 2022 केवल पहला नववर्ष नहीं, बल्कि नए भारत की अमृत यात्रा की मजबूत नींव का वर्ष होने जा रहा है। एक मजबूत संकल्प के साथ नए भारत की परिभाषा गढ़ी जा रही है, जहां यह विशेष अवसर एक तरफ भारत की जीवन यात्रा में आजादी के इतिहास के लोकतांत्रीकरण का नया अध्याय लिख रहा है, वहां दूसरी तरफ अब किंतु-परंतु के बिना विकास यात्रा को अपनी पूर्णता तक पहुंचाने के संकल्पों से लैस है, ताकि जब देश आजादी के सौ साल पूरे करे, देशवासियों के लक्ष्य यथार्थ में बदलें और 21वीं सदी का नया भारत स्वामी विवेकानंद के सपनों का गौरव हासिल कर बने विश्व गुरु। ऐसे में अमृत काल के पहले नववर्ष की शुरुआत में यह समझते हैं कि 2047 में कैसा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों का भारत...

राष्ट्र की प्रगति

प्रति 1 मिनट में भारत...

भारत का सामर्थ्य ही है कि आज एक मिनट में कई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। साथ ही प्रगति के पथ पर निरंतर हो रहा अग्रसर...

09
वाहनों का निर्यात किया गया।

197 लोग काम से जोड़े गए।

7.74 लाख डॉलर का माल निर्यात किया गया।

50
वाहनों का निर्माण हुआ।

5275
कोविड वैक्सीन के डोज दिए गए।

1.7
लाख डॉलर की एफडीआई मिली

1300
इंटरनेट यूजर जोड़े गए।

609
मोबाइल फोन का निर्माण हुआ।

14 लोगों को आयुष्मान भारत से लाभ।

9.5 करोड़ रुपये की जीडीपी तैयार कर रहा।

15 करोड़ रुपये मूल्य का यूपीआई लेनदेन हुआ।

2200 मोबाइल कनेक्शन जोड़ा।

पहली बार

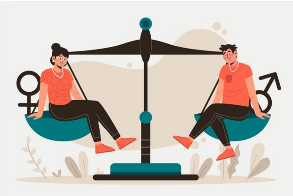

1020

हुआ भारत में पहली बार 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का अनुपात।

800

बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था 2014 के 10वें पायदान के मुकाबले 6वें पायदान पर आई।

- ऑटोमोबाइल मार्केट में मैक्सिको को पछाड़कर भारत 2014 के 7वें स्थान से 6वें स्थान पर आया।
- वियतनाम, कोरिया, अमेरिका को पछाड़ भारत दुनिया में अग्रणी स्मार्टफोन निर्माताओं में से एक बना। वैश्विक स्तर पर मेक इन इंडिया उत्पादों की भारी मांग हो रही है।
- दुनिया की तमाम एजेंसियां भारत की जीडीपी में वृद्धि के अपने ही अनुमान को बढ़ाने को मजबूर हुई हैं।
- उज्ज्वला, पक्के मकान, आयुष्मान भारत जैसी पहल गरीबों को बेहतर जीवन स्तर दे रही हैं।

400

बिलियन डॉलर के पार होने की उम्मीद है निर्यात में वृद्धि मौजूदा वित्त वर्ष में।

10

शीर्ष देशों में शामिल हुआ कृषि उत्पादों के निर्यात के मामले में भारत।

- सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक नया भारत पश्चिमी देशों के मुकाबले बेहतर। वर्ल्ड "गिविंग" इंडेक्स में व्यापक सुधार के साथ रैंकिंग 2014 में 69वीं थी जो अब 14वीं हुई।
- इस्पात रैंकिंग में भारत 2014 के चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा।
- इनोवेशन रैंकिंग में भारत 30 अंक का सुधार करते हुए 2014 के 76वें स्थान की जगह अब 46वें स्थान पर पहुंचा।
- विश्व पर्यटन रैंकिंग में 2013 के 65वें स्थान के मुकाबले 34वें पर पहुंचा।
- विश्व में सौर ऊर्जा संयंत्रों की संख्या रैंकिंग में भारत 2014 में 10वें स्थान पर था, अब दूसरे स्थान पर आया।

आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे भारत की विकास यात्रा में ये उपलब्धियां केवल एक पड़ाव मात्र है, पूर्णता नहीं। वर्ष 2014 से अब तक की यात्रा अब अमृत काल की मजबूत नींव बन रही है तो भविष्य का भारत अपनी उच्च आकांक्षाओं को पूरा करने को संकल्पबद्ध है। अपने यहां कहा गया है- 'उत्सवेन बिना यस्मात् स्थापनम् निष्फलम् भवेत्' अर्थात, कोई भी प्रयास, कोई भी संकल्प बिना उत्सव के सफल नहीं होता। संकल्प चाहे नए साल का हो या फिर अमृत काल में भारत को विश्व गुरु बनाने का, जब वह उत्सव की शक्ल लेता है तो उसमें लाखों-करोड़ों के संकल्प और ऊर्जा उसे साकार करने में जुट जाती है। इसे साकार करने में भारत की सबसे बड़ी शक्ति युवाओं की है। भारत दुनिया का सबसे अधिक युवा देश है, जहां औसत आयु 29 वर्ष है और यही युवा शक्ति भारत को सशक्त बनाने की सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद जी जब भारत के भविष्य की बात करते थे, तो अपनी आंखों के सामने मां भारती की भव्यता का दर्शन करते थे और कहते थे- जहां तक हो सके, अतीत की ओर देखो। पीछे जो चिर नूतन झरना बह रहा है, आकंठ उसका जल पियो, फिर आगे बढ़ो और भारत को पहले से भी कहीं ज्यादा उज्ज्वल, महान, श्रेष्ठ बनाओ।

आजाद भारत में पैदा हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर भारत को एक नई दिशा देने का बीड़ा उठाया तो उनका संदेश भी स्पष्ट था- अब देश धीमी रफ्तार से चल नहीं सकता, टूटा-फूटा, आधा-अधूरा नहीं चल सकता। छोटा-छोटा काम करके पूरा नहीं हो पाएगा, बल्कि जो भी करना होगा वो बड़ा ही करना पड़ेगा। इसी सोच ने भारत के सामान्य मानव का मन बदला है और उसकी वजह से देश आज संकल्प भी लेता है और सिद्धि भी हासिल कर रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को वैभवशाली बनाने की संकल्प यात्रा शुरू की है, जिसे अमृत काल नाम दिया है।

ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता

*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने **चैंपियन ऑफ अर्थ** से सम्मानित किया है जो इस नए ऊर्जा स्रोत के दोहन में भारत के बढ़ते आदर्शवादी नेतृत्व की एक पहचान है। भारत की प्रगति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए भारत का ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना समय की मांग है।*

अमृत वर्ष

गैर जीवाश्म स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन में भारत ने 40 फीसदी का लक्ष्य हासिल किया है।

12 **लाख करोड़ रुपया से भी अधिक सालाना खर्च करता है भारत एनर्जी आयात के लिए।**

85 **प्रतिशत आयात करता है। भारत अपनी कुल पेट्रोलियम और दूसरी ऊर्जा जरूरतों का करीब।**

- प्राकृतिक गैस के मामले में आधी जरूरतें विदेश से होने वाली आपूर्ति से होती है। 16% से अधिक वैश्विक आबादी के साथ, हम वर्तमान में दुनिया की प्राथमिक ऊर्जा का केवल 6% उपयोग कर रहे हैं। 05% कार्बन उत्सर्जन भारत का है। जबकि दुनिया की आबादी में 17 फीसदी हिस्सेदारी।

स्वर्णिम काल

- ऊर्जा सुरक्षा के लिए हमारी खोज उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और स्वीकार्यता के ढांचे के तहत काम करेगी, जो सस्ती कीमत पर सभी वर्गों और क्षेत्रों के लिए ऊर्जा सुलभ बनाना है।
- गैस आधारित अर्थव्यवस्था, सीएनजी, पीएनजी का नेटवर्क, 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा और 2030 तक रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला सेक्टर बनाने का लक्ष्य है।
- 2023 तक भारतीय रेल मार्गों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है।
- भारत 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता का निर्माण करके और 2030 तक 450 गीगावॉट तक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता का अनुसरण कर रहा है। इसमें से 100 गीगावाट के लक्ष्य को भारत ने तय समय से पहले हासिल कर लिया है।

जन इतिहास से प्रेरणा

चरखा और नमक की तरह जयंतियां व विशेष अवसर बन रहे विकास यात्रा के नए प्रतीक

आजादी के आंदोलन में जन साधारण की बड़ी सहभागिता रही है। लेकिन उन सभी को वैसी पहचान नहीं मिली, जितनी मिलनी चाहिए थी। ऐसे में गांधी जी के चरखा और नमक की तरह की प्रतीकों का बेहतर इस्तेमाल और अमृत महोत्सव के साथ आजादी के इतिहास के लोकतांत्रीकरण की शुरुआत हो चुकी है..

अमृत वर्ष

- विशेष उपलक्ष्यों और महापुरुषों की जयंती को जन सहभागिता का अवसर बनाया गया।
- स्वच्छता आंदोलन को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से जोड़कर देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेकर जन आंदोलन खड़ा किया गया।
- आजादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव नाम दिया गया और विशेष कमेटी बनाकर आयोजन किया गया।
- गुमनाम नायकों की कहानी लिखने के लिए युवाओं को प्रेरित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को एक अवसर बनाया गया।
- जनजातीय गौरव के लिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया।
- सुहेलदेव, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे कई महापुरुषों के योगदान का स्मरण कर आजादी के आंदोलन की एक नई पीठिका तैयार करनी शुरू की गई।

स्वर्णिम काल

- वर्ष 1947 की तरह ही 2022 यानी 75वें वर्ष को एक आधार की तरह तैयार किया जा रहा, ताकि 2047 तक भारत के नए संकल्पों को साकार करने की प्रेरणा मिले।
- आजादी का आंदोलन सिर्फ अंग्रेजी शासन काल तक सीमित नहीं है, उससे पहले भी भारत गुलामी के कालखंड से गुजरा है। ऐसे में उन सभी महापुरुषों के योगदान को बाहर लाने की पहल।
- देश के हर कोने, वर्ग के योगदान को भी देश के सामने लाना है। कई ऐसे लोग हैं जो कोई न कोई महान काम कर रहे हैं। उनकी सोच को सामने लाना और देश को उनके प्रयासों से जोड़ा जाएगा।
- आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्तियुग में समाई हुई है। भक्ति आंदोलन ने जैसे आजादी के आंदोलन ने ताकत दी, उसी तरह आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने में उन महापुरुषों की प्रेरणा को 'वोकल फॉर लोकल' का आधार बनाया जा रहा है।
- देश में आध्यात्मिक चेतना जागृत हो रही है। आध्यात्मिक चेतना को 75वें वर्ष के एक आधार की तरह तैयार किया जा रहा। ताकि 2047 तक भारत के नए संकल्पों को साकार करने की प्रेरणा मिले।

विकसित भारत की ऐसे तैयार हो रही पीठिका

इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जाग्रत रहता है, जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परम्पराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है और उसे संस्कारित बना निरंतर प्रेरित करता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के 75 वर्ष को एक ऐसे महायज्ञ के रूप में बदल दिया है, जहां आजादी के इतिहास का लोकतांत्रीकरण भी हो रहा है। आजादी के आंदोलनों में जन साधारण की सहभागिता को प्रतीकों और अवसरों के जरिए प्रधानमंत्री ने नई दिशा दी है। जिस तरह महात्मा गांधी ने चरखे और नमक को आंदोलन का प्रतीक बना दिया था, उसी तरह नए भारत में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने की बात हो या फिर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने, नेताजी सुभाषचंद्र बोस की 125वीं जयंती, आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में गुमनाम नायकों की कहानी लिखने-सुनाने को लेकर आयोजन

आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए तेल और गैस क्षेत्र के प्रबंध में स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया जा रहा।

स्वास्थ्य समृद्धि की ओर भारत

हर गरीब तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने की गति तेज हुई है तो कोविड की चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार अब स्वास्थ्य का ऐसा ढांचा खड़ा करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे भविष्य में कभी भी इस तरह की महामारी से निपटने के लिए देश रहे तैयार।

COV
RAT
TECH

अमृत वर्ष

137%

की बढ़ोतरी के साथ 2.40 लाख करोड़ रुपया किया गया स्वास्थ्य बजट को। स्वास्थ्य बजट पहली बार केंद्र सरकार के एजेंडे में सर्वोच्च प्राथमिकता बना।

डिजिटल हेल्थ आईडी

आत्मनिर्भर भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत। हर नागरिक को डिजिटल हेल्थ आईडी। इसमें पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा।

नि:शुल्क टीका

बीमारियों के खिलाफ निशुल्क टीका प्रदान किया जा रहा है यूआईपी योजना के तहत।

कीर्तिमान

कोविड टीकाकरण में वैश्विक कीर्तिमान स्थापित। लोगों को सुरक्षा चक्र दे रही है केंद्र सरकार।

- स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाने के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना (स्वास्थ्य बीमा योजना), आयुष्मान स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, जेनेरिक दवाओं के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन आदि जैसी योजनाएं क्रांतिकारी बदलाव ला रही है।

आदि और अब अमृत काल का संकल्प। इसका उद्देश्य स्वाधीनता संग्राम के जाने-पहचाने नायकों के साथ-साथ उन सेनानियों की जीवनगाथा को जन-जन तक पहुंचाना है, जिन्हें इतिहास में उतनी जगह नहीं मिली। देश के हर कोने, हर वर्ग के योगदान को भी देश के सामने लाना है।

इसमें संदेह नहीं कि आजादी के आंदोलन ज्योति को निरंतर

स्वर्णिम काल

1.5 लाख हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे आयुष्मान भारत योजना के तहत। अभी तक 75 हजार से ज्यादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनाए जा चुके हैं।

736 जिलों में बाल चिकित्सा इकाइयां और हर राज्य में उत्कृष्ट बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित होंगे विशेष पैकेज के जरिए।

602 **जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट की शुरुआत होगी।**

- सरकार 'संपूर्ण स्वास्थ्य' विषय पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सभी नागरिकों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा।
- कोविड काल से मिली सीख के बाद केंद्र सरकार संक्रामक बीमारियों का पता लगाने और रोकथाम के लिए उपचार का मजबूत ढांचा तैयार करेगी।
- देश भर में गांव से लेकर जिला, प्रदेश तक स्वास्थ्य का पूरा ढांचा खड़ा होगा ताकि लोगों को नजदीक में स्वास्थ्य की सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हो।
- बीमारियों का उपचार की बजाए रोकथाम पर विशेष जोर देते हुए राष्ट्रीय आयुष मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ-साथ नए आयुष अस्पतालों का निर्माण और चिकित्सा के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

अमृत वर्ष

100 **करोड़ डोज** इंडिया का नया रिकॉर्ड बना है। विश्व का सबसे तेज टीकाकरण अभियान के तहत सिर्फ 9 माह में वैक्सीन के 100 करोड़ डोज लगाए गए।

- कोविन एप के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल टीकाकरण अभियान में 86 करोड़ पंजीकरण हुआ।
- 17 सितंबर 2021 को दुनिया में एक दिन में अब तक का सबसे अधिक 2.5 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाए गए।
- 138 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, इस वर्ष संपूर्ण टीकाकरण के साथ भविष्य के लिए भी स्वास्थ्य का सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा।
- शुरुआती 85 दिनों में 10 करोड़ डोज लगाने की तुलना में अब देश केवल 15 दिनों में 10 करोड़ डोज लगाने में सक्षम।
- भारत में कोविड का पहला मामला आने के 11 महीनों के भीतर दो मेक इन इंडिया वैक्सीन- कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दी।
- जनसामान्य तक कोविड वैक्सीन की डिलिवरी सुनिश्चित हुई। वैक्सीन डिलिवरी के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल।
- आईसीएमआर ने टीकों की डिलिवरी के लिए '**I-Drone**' लांच किया, वर्तमान में मणिपुर, नगालैंड व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका इस्तेमाल।
- समग्र अभियान में डाकघर, स्कूल, आंगनवाड़ी आदि द्वारा अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मदद।

स्वर्णिम काल

- कोविड के खिलाफ जंग में निर्णायक लड़ाई के लिए देश के सभी नागरिकों को टीका लगाया जाएगा।
- नई वैक्सीन को भी मंजूरी दी जा रही है और जल्द ही बच्चों का टीकाकरण भी शुरु होगा।
- टीकाकरण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल देश के अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाएगा, ताकि टीकाकरण का अभियान और तेज किया जा सके। टीकाकरण में नई-नई तकनीकों का भी इस्तेमाल हो रहा है।
- जनभागीदारी ने फिर अपनी ताकत दिखाई है और हर घर दस्तक कार्यक्रम ने टीकाकरण को जबरदस्त गति प्रदान की है, इसे आगे और नए आयाम दिए जा रहे हैं।

जागृत करने का काम, पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण, हर दिशा में, हर क्षेत्र में, देश के संतों-महंतों-आचार्यों ने निरंतर किया था। पूर्व में चैतन्य महाप्रभु, राम कृष्ण परमहंस और श्रीमंत शंकर देव जैसे संतों के विचारों ने समाज को दिशा दी। पश्चिम में मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, नरसी मेहता हुए, उत्तर में संत रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानकदेव,

पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 138 करोड़ से अधिक वैक्सीन दी जा चुकी है भारत में।

संत रैदास, दक्षिण में मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य हुए, भक्ति काल के इसी खंड में मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, सूरदास, केशवदास, विद्यापति जैसे महानुभावों ने अपनी रचनाओं से समाज को अपनी कमियां सुधारने के लिए प्रेरित किया। इसी से एक आध्यात्मिक चेतना का पीठ बल खड़ा हुआ जिसने 1857 की क्रांति को जन्म दिया था। एक प्रकार से भक्ति आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता आंदोलन की पीठिका तैयार की थी।

एक बार फिर देश में आध्यात्मिक चेतना जागृत होती हुई दिख रही है जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण की नींव बनने का काम कर रही है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए सिरे से परिभाषित करता है। खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। भारत की विकास यात्रा में भी 2022 वही वर्ष है। आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन 75 वर्षों की उपलब्धियों को भी दुनिया के सामने रखने और अगले 25 वर्षों के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है। वर्ष 2022, आजाद भारत के 100 वर्ष के लिए नए संकल्पों का आधार बन रहा है। जिसका लक्ष्य है- भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गावों और शहर को बांटने वाला न हो। एक ऐसे भारत का निर्माण, जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल न दें। एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो।

नवनिर्माण की ओर बढ़ता भारत

भारत को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम हो या फिर गरीबों, मजदूरों को गांव में ही अनाज और रोजगार दिलाना, युवा शक्ति को स्टार्ट अप से जोड़ना या मध्यम वर्ग, महिलाएं समेत समाज के हर वर्ग को

वैक्सीन मैत्रीः दुनिया के लिए भारत की संजीवनी

अमृत वर्ष

- **20 जनवरी 2021 को वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत अन्य देशों को वैक्सीन डोज उपलब्ध कराना शुरू किया गया।**
- **14 अक्टूबर 2021 को वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम को एक बार फिर से शुरू किया गया। इसके अंतर्गत नेपाल, म्यांमार, ईरान और बांग्लादेश में से प्रत्येक को 10 लाख वैक्सीन डोज प्रदान किए गए।**
- **वर्तमान में 96 देशों को मेड इन इंडिया टीकों का निर्यात किया जा रहा है।**

स्वर्णिम काल

500 करोड़ वैक्सीन डोज दुनिया को उपलब्ध कराएगा आने वाले दिनों में भारत।

- मेक इन इंडिया वैक्सीन में दुनिया का भरोसा बढ़ा है। डब्लूएचओ समेत दुनिया के 125 से अधिक देश भारत की स्वदेशी वैक्सीन का लोहा मान चुके हैं।
- जनभागीदारी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता भारत वैक्सीन निर्यात करने के साथ-साथ छोटे देशों को मानवीय सहायता का धर्म भी निभाएगा।
- ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के आने के बाद अफ्रीकी देशों को भारत ने मदद शुरू की है, इसे आगे बढ़ाया जाएगा ताकि मानवता की रक्षा में भारत की अग्रणी भूमिका कायम रहे।

समाज के आखिरी व्यक्ति तक विकास और आत्मसम्मान

बीते सात वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को मिला है। उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत की ताकत आज देश का हर गरीब जानता है। आज सरकारी योजनाओं की गति बढ़ी है और वह निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। पहले की तुलना में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब विकास को पूर्णता तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ योजनाओं को अंजाम दे रही है केंद्र सरकार

अमृत वर्ष

80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन कोविड काल में।

02 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के मकान

10 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय का निर्माण

43 करोड़ से अधिक जन-धन खाते से सामाजिक सुरक्षा

- 8 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन. कवरेज 99.6 फीसदी तक पहुंचा। 2300 करोड़ रुपये का लाभ 23 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को स्वनिधि योजना के तहत।
- 11.4 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 1.6 लाख करोड़ रु. से अधिक की सम्मान निधि 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपये की मुफ्त ईलाज की सुविधा- आयुष्मान भारत।
- जल जीवन मिशन के सिर्फ दो वर्ष में 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया है।

स्वर्णिम काल

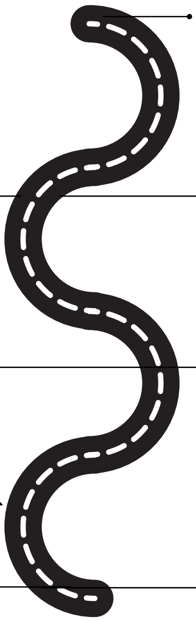

अमृत यात्रा के जरिए स्वर्णिम वर्ष तक शत-प्रतिशत गांवों में सड़कें हों।

शत-प्रतिशत परिवारों के बैंक अकाउंट हो।

उज्ज्वला 2.0 के जरिए शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को गैस कनेक्शन।

100 प्रतिशत लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड हो।

सरकार की बीमा योजना-पेंशन योजना-आवास योजना से देश का हर पात्र नागरिक जुड़े।

स्वनिधि योजना से देश के हर रेहड़ी-पटरी वाले अपनी आजीविका से जुड़ें।

विकास की मुख्यधारा में लाना, प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकताओं में है। दशकों तक नियति के भरोसे रहा देश अब समग्र विकास की सोच और तकनीक से प्रगति पथ पर अग्रसर है। विज्ञान और तकनीक भारत के विकास का ऐसा उपकरण बन गया है कि प्रशासनिक सुधार, बिजली, रेल सुधार, भ्रष्टाचार पर अंकुश, टैक्स पारदर्शिता, जीएसटी से एक देश-एक टैक्स, स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, किसानों-महिलाओं के हित में कदम, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव से लेकर रक्षा आधुनिकीकरण और दशकों से लंबित ऐसी परियोजनाएं साकार हो रही हैं जो पहले असंभव लगते थे।

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को साल 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी।

प्रगति पथ पर बढ़ रहे देश के सामने और विश्व में पूरी मानव जाति के सामने कोविड का ये कालखंड बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया। लेकिन देश ने बहुत संयम, धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ा भी है। इस लड़ाई में चुनौतियों के बावजूद हर क्षेत्र में

असीम संभावनाएं

दुनिया का सबसे युवा देश भारत

भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और उसकी आबादी मानव संसाधन है। जहां पश्चिमी देश और यूरोपियन देशों में बुजुर्ग आबादी की संख्या बढ़ रही है, उस लिहाज से भारत के पास प्रचुर संभावनाएं उसकी युवा जनसंख्या ही है। युवाओं की आकांक्षाएं और राष्ट्र के लिए कुछ करने की इच्छाशक्ति नए भारत की मजबूत आधारशिला है जो स्वर्णिम वर्ष के संकल्पों को करेगी साकार।

50,000

भारत में पहले स्टार्ट अप शब्द गाहे-ब-गाहे ही सुनने को मिलते थे। लेकिन बीते सात साल में भारत में स्टार्टअप का नया युग शुरू हुआ और आज 50 हजार से अधिक स्टार्ट अप भारत में चल रहे हैं।

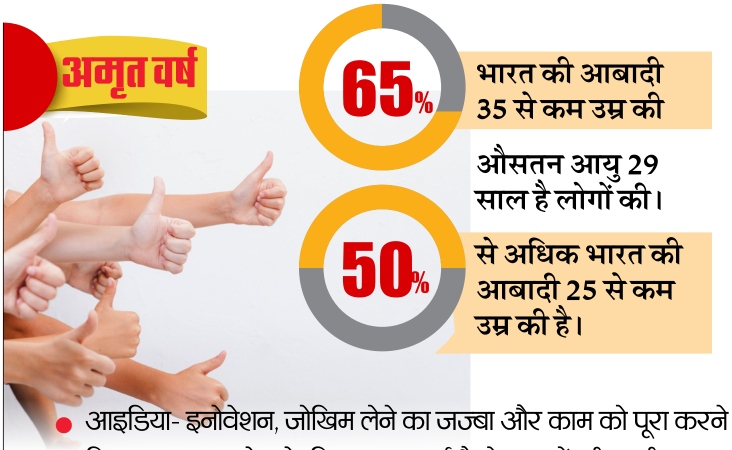

65% भारत की आबादी 35 से कम उम्र की

औसतन आयु 29 साल है लोगों की।

50% से अधिक भारत की आबादी 25 से कम उम्र की है।

- आइडिया- इनोवेशन, जोखिम लेने का जज्बा और काम को पूरा करने की जिद्द, यह समृद्ध देश के लिए महत्वपूर्ण है तो युवाओं की सच्ची पहचान।
- स्टार्ट अप के जरिए देश का युवा नौकरी मांगने वालों की बजाए नौकरी देने वाला बन रहा है और स्टार्टअप में निवेश लगातार बढ़ रहा है।
- भारत अब स्टार्ट अप से आगे बढ़ते हुए यूनीकॉर्न की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि जिसका मूल्यांकन 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है। पहले भारत में 1-2 यूनीकॉर्न हुआ करते थे, लेकिन अब इसकी संख्या 70 के पार हो चुकी है।
- सिर्फ कोविड काल के पिछले 10 महीने में ही हर 10 दिन में एक नया यूनीकॉर्न बना है।
- टोक्यो ओलंपिक में भारत ने एक स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीता। अब तक ओलंपिक खेलों में यह भारतीय खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पैरालंपिक खेलों में अबकी बार भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया।

पीएम मोदी के स्किल, रिस्किल और अपस्किल मूलमंत्र के साथ अब भारतीय युवा बन रहे आत्मनिर्भर।

देशवासियों ने असाधारण गति से काम किया है। वैज्ञानिकों, उद्यमियों की ताकत का ही परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए आज किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना पड़ा। जबकि एक समय था कि वैक्सीन के लिए विदेशों पर वर्षों निर्भर रहना पड़ता था। कोविन जैसी ऑनलाइन व्यवस्था, डिजिटल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था आज दुनिया को आकर्षित कर रही है। महामारी के समय भारत जिस तरह से 80 करोड़ देशवासियों को महीनों तक लगातार मुफ्त अनाज देकर गरीब के घर के चूल्हे को जलाने के निर्णय से दुनिया अचरज में भी है और यह चर्चा का विषय भी है।

2047 के भारत की सुनहरी तस्वीर

बीते सात वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है। उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान भारत की ताकत आज देश का हर गरीब जानता है। आज सरकारी योजनाओं की गति बढ़ी है। वह निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। पहले की तुलना में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन यह सफर यहीं पूरी नहीं होती है। देश को पूर्णता तक जाना है। इसी संकल्प के साथ भारत ने अमृत काल की यात्रा प्रारंभ की है जहां शत-प्रतिशत गांवों में सड़कें हों, शत-प्रतिशत परिवारों के बैंक अकाउंट हो, शत-प्रतिशत लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड हो, शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन हों। सरकार की बीमा योजना हो, पेंशन योजना

स्वर्णिम काल

भारतीय रेल कौशल विकास परियोजना

50,000

से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। कौशल विकास को बढ़ावा देते हुए साल 2024 तक।

अटल टिंकरिंग लैब का दायरा अब बढ़कर

9000

स्कूलों तक पहुंचा है और अब उसे 10 हजार से अधिक विद्यालयों तक पहुंचाया जाएगा।

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में हजारों आइडियाज

1000000

से अधिक छात्रों, 7 हजार से अधिक संस्थानों से 6 हजार आइडिया आए। इसे और गति प्रदान की जाएगी।

मुफ्त कौशल प्रशिक्षण

46 लाख से अधिक महिलाएं, 45 हजार से अधिक दिव्यांगजन सशक्त हुए, इसे शत-प्रतिशत पहुंचाया जाएगा।

ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ हो भारत

भारत को ओलंपिक खेल के मामले में 2028 तक दुनिया के श्रेष्ठ 10 देशों की सूची में लाना। 2021-25 तक खेलों के लिए अलग से 8750 करोड़ रु. का प्रावधान।

- पोडियम स्कीम से 2028 के लॉस एंजेल्स ओलंपिक तक की तैयारी। नई शिक्षा नीति में खेलों को पाठ्येतर की जगह मुख्यधारा पढ़ाई का हिस्सा बनाया। खेलों में टैलेंट, टेक्नोलॉजी और पेशेवर बनाने के लिए जो अभियान चल रहा है इस दशक में उसे और तेज और व्यापक किया जाना है।
- नई शिक्षा नीति के तहत 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि स्कूल स्तर पर अर्जित व्यावसायिक कौशल को उच्च शिक्षा स्तर तक ले जाया जा सके।

दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप भारत में। इनोवेशन के जरिए युवाओं को मिल रहे नए अवसर।

हो, आवास योजना से हर उस व्यक्तियों को जोड़ना है जो उसके हकदार हैं। पटरी पर बैठकर, फुटपाथ पर बैठकर सामान बेचने वालों को स्वनिधि योजना के जरिए बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। देश आज हर घर जल मिशन को लेकर तेजी से काम कर रहा है। जल जीवन मिशन के सिर्फ दो-ढ़ाई वर्ष में 5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल मिलना शुरू हो गया है।

देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। गरीब महिलाओं, गरीब बच्चों में कुपोषण और जरूरी पौष्टिक पदार्थो की कमी, उनके विकास में बड़ी बाधा बनती है। इसे देखते हुए सरकार ने गरीबों को पोषणयुक्त चावल देने की पहल की है। वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल फोर्टिफाइ करने का भी संकल्प देश ने लिया है। अभी तक 75 हजार से ज्यादा हेल्थ-वेलनेस सेंटर बनाए जा चुके हैं। अब ब्लॉक स्तर पर अच्छे अस्पतालों और आधुनिक लैब के नेटवर्क पर विशेष रूप से काम किया जा रहा है। बहुत जल्द देश के हजारों अस्पतालों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट भी उपलब्ध हो रहे हैं। विकास की पहुंच में पीछे छूटे वर्ग हो या क्षेत्र, अब उन्हें साथ लेकर चलना होगा। मूलभूत जरूरतों की चिंता के साथ ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी हाल ही में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में, ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी वर्ग को

आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। संसद में कानून बनाकर ओबीसी से जुड़ी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है।

सर्वांगीण-सर्वसमावेशी-सर्वस्पर्शी विकास

केंद्र सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि समाज की विकास यात्रा में कोई व्यक्ति, वर्ग न छूटे, कोई भू-भाग, देश का कोई कोना भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। विकास सर्वांगीण होना चाहिए। देश के ऐसे क्षेत्रों को आगे लाने के लिए पिछले सात वर्षों में प्रयास किए गए हैं। पूर्वी भारत हो या पूर्वोत्तर या जम्मू-कश्मीर, लद्दाख सहित पूरा हिमालय का क्षेत्र हो, तटवर्ती क्षेत्र हो या फिर आदिवासी अंचल, यह भविष्य में भारत के विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार बन रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में ही परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही हैं। लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। एक तरफ लद्दाख में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है तो दूसरी तरफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का केंद्र भी बना रही है।

21वीं सदी के इस दशक में, भारत नीली अर्थव्यवस्था के अपने प्रयासों को तेजी से बढ़ा रहा है। गहरे समुद्र अभियान से समंदर की असीम संभावनाओं को तलाशने की महत्वाकांक्षा को साकार किया जा रहा है। देश के जिन जिलों के लिए ये माना गया था कि ये पीछे रह गए, हमने उनकी आकांक्षाओं को भी जगाया है। देश में 110 से अधिक आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। आकांक्षी जिले भारत के अन्य जिलों की बराबरी तक पहुंचें, उस दिशा में तेज स्पर्धा चल रही है। अर्थजगत में पूंजीवाद और समाजवाद इसकी चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन भारत सहकारवाद पर भी बल देता है। इस क्षेत्र के सशक्तीकरण के लिए अलग मंत्रालय बनाकर इस दिशा में कदम उठाए गए हैं।

गांव-किसान-मध्यमवर्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर

अमृत वर्ष

नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना

107

लाख करोड़ की परियोजना जिसमे रेल, रोड, शिपिंग , एयरपोर्ट्स, एक्सप्रेसवेज और अन्य योजनाएं शामिल हैं।

100%

की बढ़ोतरी 7 साल में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में।

राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क निर्माण

37 किमी

प्रतिदिन सड़क निर्माण कर विश्व में रिकार्ड बना रहा है भारत।

13,394

किलोमीटर सड़क बनाई भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड के बावजूद।

- भारतीय रेल ने पश्चिम मध्य रेलवे जोन की भोपाल-इटारसी तीसरी लाइन परियोजना के बारखेड़ा-बुदनी (26.50 किमी) खंड के बीच बड़ी लाइन तीसरी लाइन के लिए व्यापक तरीके से प्रमुख सुरंग निर्माण कार्य आरंभ किया है।
- भारत गौरव ट्रेनों से भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भव्य ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे।
- पीएम गति-शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत सरकार अलग-अलग मंत्रालयों को एक प्लेटफॉर्म पर ला रही है। अलग-अलग प्रोजेक्ट्स की जानकारी, हर डिपार्टमेंट को समय पर मिले, इसके लिए भी व्यवस्था बनाई गई है।
- गति शक्ति मास्टर प्लान के जरिए अब भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई दशा और दिशा की ओर बढ़ चला है।
- प्रधानमंत्री गतिशक्ति का नेशनल मास्टर प्लान सौ लाख करोड़ से भी अधिक की यह योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आई है।

> आजाद भारत की सबसे बड़ी गतिशक्ति योजना से लटकाने, अटकाने और भटकाने की समस्या से आगे बढ़ा देश।

इंफ्रास्ट्रक्चर
बदलेगी राष्ट्र की दशा-दिशा

इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर जो ना सिर्फ देश को विकास के पथ पर ले जाता है बल्कि रोजगार का अवसर भी पैदा करती है। इतना ही नहीं आधुनिक विश्व में प्रगति की बुनियाद, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ी होती है। साथ ही यह मध्यमवर्ग की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की भी पूर्ति करता है।

स्वर्णिम काल

111 लाख करोड़ की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का विस्तार 7,400 परियोजनाओं को कवर करने के लिए।

02 लाख किमी लंबाई तक किया जाएगा एनएचआई द्वारा निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार साल 2024-25 तक।

स्वर्णिम काल

अमृत महोत्सव

75
नई वंदे भारत ट्रेनें देशभर में चलाने को प्रयासरत रेलवे आने वाले 2 सालों में।

गति शक्ति योजना

220
हो जाएगी एयरपोर्ट/हेलीपोर्ट/वाटर एयरोड्रम्स की संख्या बढ़कर साल 2024-25 तक उड़ान के अंतर्गत।

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति से संबंधित प्रोत्साहन और दंडात्मक कार्रवाई पर अधिसूचना जारी की। जो पहली अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी।

- देश में अन्य 19 जगहों पर आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा विकसित की जाएगी। इनमें राजस्थान में फलोदी-जैसलमेर सड़क व बाड़मेर-जैसलमेर सड़क, पश्चिम बंगाल में खड़गपुर - बालासोर सड़क, खड़गपुर-क्योंझर सड़क व पानागढ़/केकेडी के पास, तमिलनाडु में चेन्नई, पुडुचेरी सड़क पर, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर- ओंगोल सड़क व ओंगोल - चिलकालुरिपेट सड़क पर, हरियाणा में मंडी डबवाली से ओधन सड़क पर, पंजाब में संगरूर के नजदीक, गुजरात में भुज-नलिया सड़क और सूरत-बड़ोदा सड़क पर, जम्मू और कश्मीर के बनिहाल-श्रीनगर सड़क, लेह/न्योमा क्षेत्र में, असम में जोरहाट-बाराघाट सड़क पर, शिवसागर के नजदीक, बागडोगरा-हाशिमारा सड़क पर और असम में हाशिमारा-तेजपुर मार्ग व हाशिमारा-गुवाहाटी सड़क हैं।

गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क डाटा की ताकत पहुंच रही है। गांवों में स्वसहायता समूह से 8 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। आज जब देश वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। स्वामित्व योजना से गांवों को सामर्थ्य बनाया जा रहा है। देश के 80 प्रतिशत से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास दो हेक्टयर से भी कम जमीन है। इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उतना पहले नहीं दिया गया। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं।

नए जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए समन्वित प्रयास हो रहा है।

विश्व की सबसे बड़ी अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिल रहा अनाज।

इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की शुरुआत कर दी गई है। आधुनिक विश्व में प्रगति की बुनियाद, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही खड़ी होती है जो मध्यमवर्ग की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की भी पूर्ति करते हैं। इसी बात को समझते हुए जल, थल, नभ, हर क्षेत्र में देश ने असाधारण स्पीड और स्केल पर काम करके दिखाया है। नए जलमार्ग, वाटरवेज हों, नए-नए स्थानों को सी प्लेन से जोड़ना हो, देश में बहुत तेजी से काम चल रहा है। भारतीय रेलवे भी तेजी से आधुनिक अवतार में ढल रही है।

पूर्वोत्तर-पूर्वी भारत में विकास की रोशनी

पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत का नया इतिहास लिखा जा रहा है जो दिलों को भी जोड़ रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने वाला है। एक्ट-ईस्ट पॉलिसी पूर्वोत्तर आज बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण-पूर्वी एशिया से भी जुड़ रहा है। बीते वर्षों में जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से अब पूर्वोत्तर में स्थाई शांति के लिए, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए उत्साह अनेक गुना बढ़ा हुआ है। इस क्षेत्र में पर्यटन, खेल, जैविक खेती, हर्बल दवाइयां आदि की भरपूर क्षमता है। इसे विकास यात्रा का हिस्सा बनाते हुए अमृत काल के कुछ दशक में ही इसे पूरा करने का भी संकल्प लिया गया है।

सुशासन का नया अध्याय

कोविड के बाद उभरी नई आर्थिक परिस्थितियों में मेक इन इंडिया को स्थापित करने के लिए देश ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) की भी घोषणा की है। इस योजना से जो बदलाव आया है उसका उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है। सात साल पहले भारत लगभग आठ बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन आयात करता था। अब तीन बिलियन डॉलर के मोबाइल फोन निर्यात भी कर रहा है। विनिर्माण क्षेत्र को भारत का ब्रांड एंबेसडर बनाने की सोच से

सही पोषण-देश रोशन
अब पोषणयुक्त चावल

पोषण अभियान के जरिए केंद्र सरकार ने कुपोषण के खिलाफ अभियान छेड़ा तो अब पोषण 2.0 के जरिए मिशन को आगे बढ़ाया गया है। इसी कड़ी में गरीबों के पोषण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब अपनी अलग-अलग योजनाओं के तहत पोषणयुक्त चावल देने का निर्णय भी लिया है..

अमृत वर्ष

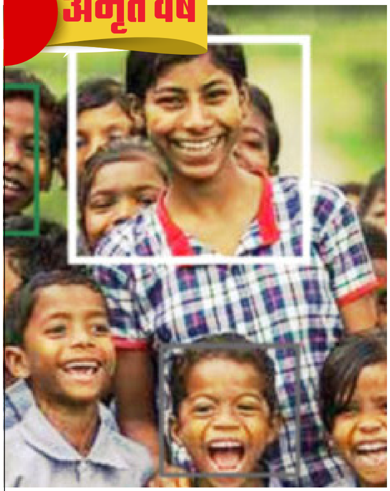

- **केंद्र विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र नागरिकों को चावल भी देती है।**
- **खाद्य सुरक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को सस्ती दरों पर या कोविड काल में मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया ताकि उन्हें खाद्य और पोषण की सुरक्षा मिले।**

- पोषण के लिए 2020 के विश्व खाद्य दिवस के मौके पर 17 और 2021 में 35 जैव संवर्धित किस्मों के बीज राष्ट्र को समर्पित किया।
- कृषि क्षेत्र को अनुसंधान और तकनीक से जोड़ा गया है ताकि उन्नत किस्मों के बीज से पोषण अभियान को मजबूती मिले।

स्वर्णिम काल

- सरकार ने तय किया गया है कि अपनी अलग-अलग योजनाओं के तहत जो चावल गरीबों को देती है, उसे पोषणयुक्त करेगी।
- 2024 तक पूरी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति होगी ताकि गरीबों को पोषणयुक्त चावल मिले।
- राशन की दुकान पर मिलने वाला चावल हो, मिड-डे मील में बालकों को मिलने वाला चावल हो, वर्ष 2024 तक हर योजना के माध्यम से मिलने वाला चावल पोषणयुक्त कर दिया जाएगा।

मिशन पोषण 2.0

मिशन पोषण 2.0 की घोषणा आम बजट में की गई है, अब केंद्र सरकार आने वाले दिनों में पोषक तत्वों को बढ़ाने के साथ-साथ पोषण के सभी अभियान को इस मिशन के तहत चलाएगी।

आत्मनिर्भर भारत के मूल मंत्र के साथ आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ रहा देश

आत्मनिर्भर भारत के मूल मंत्र के साथ आज भारत में 'वोकल फॉर लोकल' और 'मेड इन इंडिया' को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि, देश स्वावलंबी बन सके। साथ ही बड़े पैमाने पर स्वदेश में बने सामानों को विदेश निर्यात किया जा सके और यहां के युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बन सके। भारत सरकार आत्मनिर्भरता को एक सोच बनाने की पहल कर रही है जिससे न्यू इंडिया आत्मविश्वास से भरपूर और प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर हो सके।

अमृत वर्ष

- मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने के लिए इलेक्ट्रानिक्स और आईटी हाडवेयर, ऑटोमोबाइल, मोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ईवी बैटरी सहित 13 चिन्हित क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए।
- अगस्त 2020 के मुकाबले अगस्त 2021 में कुल निर्यात में 33 फीसदी से अधिक की वृद्धि।
- वर्ष 2013-2014 में जहां कृषि में आवंटन 21,934 करोड़ रुपया था, वहीं 2021-2022 में इसमें 5.5 गुना की वृद्धि करते हुए 1,23,018 करोड़ रुपया कर दिया गया।
- कोविड से पहले भारत में पीपीई किट का निर्माण लगभग नगण्य था। अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता बना।
- 2019-20 में 2 बिलियन डॉलर के रक्षा निर्यात का अनुमान।
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सितंबर 2021 तक करीब 30 लाख लोगों को 1,500 करोड़ रुपया से अधिक का लाभ मिला।

स्वर्णिम काल

- मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में भारत में न्यूनतम उत्पादन 5 सालों में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद।
- कंप्यूटर, स्वच्छता, पानी, बिजली सहित स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था। रोजगार को बढ़ावा, आजीविका के अवसरों को बढ़ावा।
- स्टार्टअप के जरिए युवा आत्मनिर्भर बन सके और लोगों को नौकरी देने वाला बन सके।

पीएलआई यानि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिल रही गति। प्रोडक्शन भी बढ़ा।

इस योजना को आगे बढ़ाते हुए बजट घोषणा के अनुरूप सभी 13 क्षेत्रों में लागू कर दिया गया है। आज देश के अलग-अलग सेक्टर और देश के छोटे शहरों में भी नये-नये स्टार्टअप बन रहे हैं। बड़े परिवर्तन लाने और सुधारों के लिए, राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होती है और आज दुनिया देख रही है कि भारत में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कोई कमी नहीं है। आज दुनिया इस बात की भी साक्षी है कि कैसे भारत अपने यहां सुशासन का नया अध्याय लिख रहा है।

विश्व में राष्ट्रीय सुरक्षा का जितना महत्व है वैसा ही महत्व पर्यावरणीय सुरक्षा को भी दिया जाने लगा है। भारत आज पर्यावरणीय सुरक्षा की एक मुखर आवाज है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता नए भारत की अनिवार्यता है और आजादी के 100 साल पूरे होने से पहले ऐसा करने के लिए स्पष्ट रोडमैप के साथ साकार करने का भी संकल्प भारत ने ले लिया है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था, सीएनजी, पीएनजी का नेटवर्क, 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, रेलवे का शत प्रतिशत विद्युतीकरण और 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला सेक्टर बनाने का लक्ष्य है। जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत देशों में भारत सबसे आगे है।

अमृत संकल्प का वाहक युवा

भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जहां 65 फीसदी आबादी 35 से कम उम्र की तो 50 फीसदी आबादी 25 से कम उम्र की है। जिनकी आकांक्षाएं और हौसलों में राष्ट्र के प्रति एक संकल्प है। प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं, "मैं भविष्यदृष्टा नहीं हूं, मैं कर्म के फल पर विश्वास करता हूं। मेरा विश्वास है मेरे देश के युवाओं पर, मेरा विश्वास है देश की बहनों पर, देश की बेटियों पर, देश के किसानों पर, देश के प्रोफेशनल पर। ये 'can do' जेनरेशन (कुछ कर दिखाने वाली पीढ़ी) है, ये हर लक्ष्य हासिल कर सकती है।"

21वीं सदी का आज का भारत बड़े लक्ष्य गढ़ने और उन्हें प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है। आज भारत उन विषयों को भी हल कर रहा है, जिनके सुलझने का दशकों से, सदियों से इंतजार था। अनुच्छेद 370 को बदलने का ऐतिहासिक फैसला हो, देश को टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने वाली व्यवस्था- जीएसटी हो, सेना के लिए 'वन रैंक-वन पेंशन' का निर्णय हो, राम जन्मभूमि, देश का शांतिपूर्ण समाधान यह सब बीते कुछ वर्षों में देश ने सच होते देखा है।

निश्चित तौर से अमृत काल की यात्रा नए भारत और आजादी के स्वर्णिम वर्ष की नई गाथा लिख रहा है। इन सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने की जीवटता उसकी एकजुटता है- जिसका मतलब है- "सबका प्रयास।" ●

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवेदनशील कवि हृदय से नए भारत की तस्वीर

वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है,
वो जो सामने मुश्किलों का अंबार है,
उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है,
उसी से तो मेरे हौसलों की मीनार है।
चुनौतियों को देखकर घबराना कैसा,
इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है।
चुनौतियों को देखकर, घबराना कैसा
इन्हीं में तो छिपी संभावना अपार है।
विकास के यज्ञ में परिश्रम की महक है,
यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है।
विकास के यज्ञ में, परिश्रम की महक है,
यही तो मां भारती का अनुपम श्रृंगार है।
गरीब-अमीर बनें नए हिंद की भुजाएं
गरीब-अमीर बनें नए हिंद की भुजाएं
बदलते भारत की यही तो पुकार है।
देश पहले भी चला और आगे भी बढ़ा।
अब न्यू इंडिया दौड़ने को बेताब है,
दौड़ना ही तो न्यू इंडिया का सरोकार है।

कोविड काल की छाया से मुक्त हुई अर्थव्यवस्था

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नवंबर का महीना सबसे जबरदस्त खबर लेकर आया है। पहले इस वित्त वर्ष की दूसरे तिमाही में 8.4% की जीडीपी विकास दर के आंकड़े ने दुनिया को हैरान किया तो जीएसटी कलेक्शन भी 1.31 लाख करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अर्थव्यवस्था में यह वृद्धि दर दुनिया में सबसे तेज है, वहीं जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा इतिहास में दूसरे सबसे बड़े स्तर पर है...

सात वर्ष पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली तो जीडीपी के लिहाज से देश की अर्थव्यवस्था राह भटक चली थी। कीमतें चढ़ रही थीं और विदेशी निवेश के आंकड़े ठहरे हुए थे। देश विकास आकांक्षा से ओतप्रोत था। ऐसे में अर्थव्यवस्था को एक आकार देने की चुनौती सामने थी। एक देश-एक टैक्स व्यवस्था, कॉरपोरेट टैक्स में कमी, एमएसएमई को सहायता के साथ उचित ढांचा देना, आईबीसी कोड जैसे ऐतिहासिक फैसलों का नतीजा अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बेहतरी के रूप में सामने भी आया। लेकिन कोविड काल के बीच जून की तिमाही में 24.4% के ऋणात्मक आंकड़े तक अर्थव्यवस्था नीचे गिरी तो लोगों ने कुछ सवाल उठाने शुरू कर दिए।

इन्हीं सवालों का जवाब मिला, कोविड के लॉकडाउन के बाद अक्टूबर से दिसंबर 2020 की तिमाही में जीडीपी फिर सकारात्मक आंकड़े पर लौट आई। इसके बाद देश ने फिर कोविड की दूसरी लहर की विभीषिका को देखा पर यह केंद्र सरकार के मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए उन सुदृढ़ फैसलों का ही असर था, कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो फिर एक बार चढ़ना शुरू किया तो दुनिया की उन तमाम एजेंसियों को भी अपना पूर्वानुमान बढ़ाना पड़ा, जो तब तक भारत की जीडीपी को नीचे जाता हुआ दिखा रही थीं। 30 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.4% रही है। यह न सिर्फ दुनिया के हर देश की वर्तमान जीडीपी में सबसे ज्यादा आंकड़ा है, बल्कि यह भारत के भविष्य के सपने को पूरा करने वाली उन आंकाक्षाओं का प्रतीक भी है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं-दूसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़ों के जारी होने से ठीक पहले जारी वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कहा गया था, कि तेज टीकाकरण और त्योहारी सीजन भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को गति देंगे और इसके चलते मांग-आपूर्ति के बीच का अंतर कम होगा तथा रोजगार के ज्यादा अवसरों का सृजन होगा। दूसरी तिमाही के आंकड़ों ने वित्त मंत्रालय के इन अनुमानों को सही साबित किया है।

अर्थव्यवस्था के 8 कोर सेक्टर में 5 की दर पॉजिटिव, 3 में सुधार

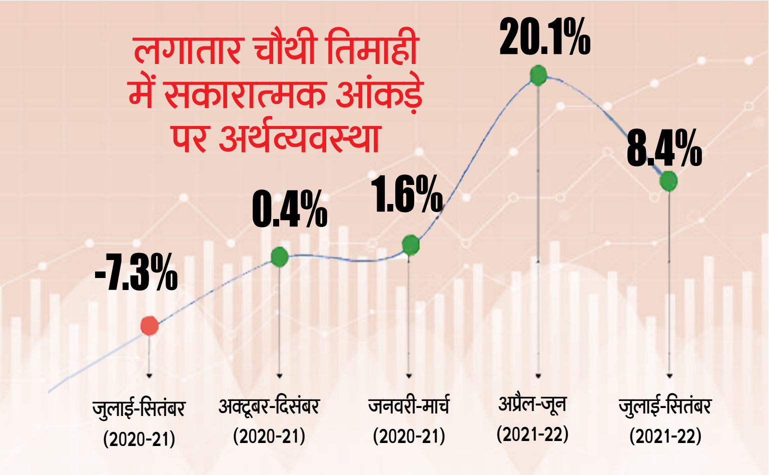

दूसरी तिमाही करोड़ रु.	2019-20	2021-22
कृषि	378602	407641+
खनन	64905	70022+
मैन्युफैक्चरिंग	564742	586775+
यूटिलिटी सर्विसेस	77469	86330+
कंस्ट्रक्शन	241188	240528-
ट्रेड, होटल, परिवहन	638065	579113-
फाइनेंस, रियल एस्टेट	862867	845468-
लोक सेवा, रक्षा व अन्य	443615	472861+

दुनिया में सबसे आगे हम

- 2021-22 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच दर्ज की गई ये विकास दर उम्मीद से बेहतर है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के कोरोना मुक्त होने का संकेत है, क्योंकि अब यह कोरोना काल से पहले से भी ज्यादा हो गई है। 2019 में अर्थव्यवस्था का आकार 35.61 लाख करोड़ रु. था। अब 35.71 लाख करोड़ रु. हो गया है।
- सबसे अधिक 15.4% वृद्धि दर माइनिंग सेक्टर में दर्ज की गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 5.5%, निर्माण गतिविधियों में 7.5% की तेजी आई। एग्रीकल्चर सेक्टर में 4.5% वृद्धि रही।
- 2020-21 की पहली तिमाही में लॉकडाउन के बाद सबसे अधिक असर कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर पड़ा था। 50.3% गिरावट के साथ इसका आकार सिकुड़कर 1.30 लाख करोड़ रुपए रह गया था। अब सवा साल बाद इस सेक्टर ने अच्छी वृद्धि दर्ज की और यह जुलाई-सितंबर तिमाही में प्री-कोविड स्तर से मात्र 660 करोड़ रुपए पीछे रह गया है
- सबसे अहम बात यह है कि भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज रही है। दुनिया के प्रमुख देश अमेरिका (4.9%), चीन (4.9%), जापान (1.4%) आदि में पिछली तिमाही में विकास दर कम रही है। भारत के बाद दूसरे स्थान पर तुर्की (6.9%) रहा है।

असंगठित क्षेत्र के औपचारीकरण की प्रक्रिया तेज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है। इससे अनौपचारिक क्षेत्र यानि असंगठित क्षेत्र के औपचारीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था में अनौपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 2020-21 में घटकर 15 से 20 प्रतिशत रह गई है, जो 2017-18 में 52.4 प्रतिशत थी। एसबीआई रिसर्च के अध्ययन के मुताबिक 2011-12 में अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने का प्रयास शुरू हुआ था, लेकिन इस प्रयास अब जोर पकड़ा है। अध्ययन से पता चला है कि 2016 से डिजिटलीकरण में तेजी और गिग अर्थव्यवस्था के उभार ने औपचारिक क्षेत्र की हिस्सेदारी को तेजी से बढ़ाया है। इसी का असर अब अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। ●

आरबीआई और एसबीआई के अनुमान से ज्यादा विकास दर

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान में 7.9% जीडीपी विकास दर की उम्मीद थी। वहीं, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक का अनुमान था कि जीडीपी की विकास दर 8.1% रह सकती है। लेकिन दूसरी तिमाही में 8.4% की जीडीपी विकास दर इन अनुमानों से भी आगे रही है।

गांव-किसान से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन तक को नया सहारा

गांवों में हर गरीब को आवास के लिए शुरू की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है तो केन-बेतवा लिंक योजना को मंजूरी के साथ केंद्र सरकार ने नदी जोड़ो अभियान के वर्षों पुराने प्रोजेक्ट को पूरा कर देश के विकास को नई गति देने की तैयारी कर ली है। यही नहीं, लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के लिए जरूरी सेमीकंडक्टर चिप पर भी आप जल्द मेड इंडिया लिखा देखेंगे। गांव-गरीब-किसान और उद्योगों से जुड़े ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण फैसलों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी...

प्रधानमंत्री आवास
ग्रामीण

- **फैसला- प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण को मार्च मार्च 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी, इसमें 2,17,257 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास' सुनिश्चित हो सकेगा।**

प्रभाव : इस योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने से यह सुनिश्चित होगा कि 'पीएमएवाई-जी'के तहत 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत शेष 155.75 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्तव 'पक्के मकानों' के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में 'सबके लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

- **फैसला : केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन-बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना की लागत 44,605 करोड़ रुपए आएगी। यह परियोजना 8 वर्षों में पूरी कर ली जाएगी।**

प्रभाव : इस परियोजना से 103 मेगावाट जल विदुत और 27 मेगावॉट की सौर ऊर्जा पैदा होगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण (केबीएलपीए)नामक विशेष प्रायोजन संस्था बनाई जाएगी। इससे मध्य प्रदेश के छत्तरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ और उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और झांसी के सूखा प्रभावित क्षेत्र और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 10.62 लाख हेक्टेयर रकबे तक की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी। नहर जुड़ने से लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिल सकेगा। कृषि गतिविधियों में वृद्धि से बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र में संकट की वजह से होने वाले विस्थापन को भी रोकने में मदद मिलेगी। इस परियोजना से पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा समग्र रूप से संभव होगी।

- **फैसला : मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का सपना होगा पूरा। 76,000 करोड़ रुपये की योजना मंजूर।**

प्रभाव : स्मार्ट फोन से लेकर आज के युग में हर इलेक्ट्रॉनिक सामान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में जाने जाने वाली सेमीकंडक्टर चिप अब भारत में भी बन सकेगी।

- 6 साल में देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का एक पूरा इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके तहत देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग और कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 76 हजार करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी गई है।
- भारत को ग्लोबल हब बनाने के लिए पीएलआई योजना के तहत 2.3 लाख करोड़ रुपये का इनसेंटिव दिया जाएगा। इसे मिशन मोड में चलाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की जाएगी।

- **फैसला: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2021 से पांच वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2026 तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी।**

प्रभाव : प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से देश के 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा, जिनमें 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्नदाता भी शामिल हैं। ●

राजधानी दिल्ली से देवभूमि तक की दूरी अब ढाई घंटे में होगी पूरी

आजादी के अमृत काल में देश ने प्रगति की रफ्तार पकड़ी है जो न रुकेगी, न थमेगी, बल्कि और अधिक विश्वास और संकल्पों के साथ आगे बढ़ेगी। 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण के साथ विश्व स्तरीय परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है। विकास यात्रा की इसी कड़ी में दिल्ली से देहरादून के बीच 210 किमी लंबी आर्थिक कॉरिडोर की प्रधानमंत्री ने रखी आधारशिला, जो यात्रा के समय को आधे से कम करेगी और उत्तराखंड की प्रगति को मिलेगी नई दिशा...

एक समय था जब पहाड़ पर रहने वाले लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का सपना ही देखते रहते थे और इसमें पीढ़ियां बीत जाती थीं। लेकिन जब कुछ करने का जुनून हो तो सूरत भी बदलती है और सीरत भी। इसी जुनून के साथ आगे बढ़ रही केंद्र सरकार कदम बढ़ा रही है ताकि अब पहाड़ का पानी और उसकी जवानी वहीं के काम आए। पहाड़ों में रहने वालों का जीवन सुगम बनाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है क्योंकि पहाड़ भारतीय संस्कृति-आस्था के गढ़ तो हैं ही, देश की सुरक्षा के भी किले हैं। इसी सोच को साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे सहित विकास की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन की इस पहल से राजधानी दिल्ली से देहरादून की दूरी अब सिमटने वाली है। मात्र ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे। इसके लिए 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से एक ऐसे कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है जो एशिया का सबसे लंबे वन्य जीव कॉरिडोर से होकर गुजरेगी। दिल्ली-देहरादून आर्थिक कॉरिडोर की लंबाई 210 किमी है, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरगनर, सहारनपुर व देहरादून जिलों से गुजरेगा। इस परियोजना को दिसंबर 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

दिल्ली के अक्षरधाम से देहरादून तक के इस आर्थिक कॉरिडोर से उत्तराखंड राज्य के पर्यटन और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इस कॉरिडोर से एक 51 किमी से लिंक मार्ग हरिद्वार को भी जोड़ेगा

प्रधानमंत्री का
संबोधन सुनने के लिए
QR कोड स्कैन करें।

विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में लगभग 18,000 करोड़ रुपये लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
- प्रधानमंत्री ने 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें 8300 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा (ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक) शामिल है।
- इससे दिल्ली से देहरादून के बीच यात्रा का समय छह घंटे से घट कर लगभग ढ़ाई घंटे का हो जाएगा।
- इसमें वन्यजीवों के लिए बिना रोक-टोक आवागमन के लिए एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव एलीवेटेड गलियारा (12 किलोमीटर) होगा।
- देहरादून में डाट काली मंदिर के पास 340 मीटर लंबी सुरंग वन्यजीवों पर होने वाले प्रभाव को कम करने में मदद करेगी।
- गणेशपुर-देहरादून खंड में वाहनों को जंगली जानवरों से टक्कर से बचाने के लिए पशुओं के लिए कई रास्ते बनाए गए हैं।
- दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे में 500 मीटर के अंतराल पर वर्षा जल संचयन और 400 से अधिक पानी के रिचार्ज प्वाइंट की व्यवस्था।
- दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे से ग्रीनफील्ड परियोजना, सहारनपुर के हलगोआ से हरिद्वार के भद्राबाद को जोड़ने वाली परियोजना का निर्माण 2000 करोड़ रु. से अधिक की लागत से किया जाएगा।
- 1600 करोड़ रु. से अधिक की लागत से बनने वाली मनोहरपुर से कांगड़ी तक हरिद्वार रिंग रोड परियोजना, हरिद्वार शहर के लोगों को, विशेष रूप से भारी पर्यटक मौसम में यातायात के जाम से राहत प्रदान करेगी और कुमाऊं क्षेत्र के साथ संपर्क में भी सुधार करेगी।
- लगभग 1700 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली देहरादून-पोंटा साहिब (हिमाचल प्रदेश) सड़क परियोजना, यात्रा के समय को कम करेगी और दोनों स्थानों के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी।
- लक्ष्मण झूले के निकट गंगा नदी पर एक पुल भी बनाया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूले का निर्माण 1929 में किया गया था, लेकिन अब इसे कम भार वहन क्षमता के कारण बंद कर दिया गया है। बनने वाले पुल पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए कांच के डेक का प्रावधान होगा, हल्के वाहनों को भी पार करने की अनुमति होगी।
- प्रधानमंत्री ने इस दौरे पर देहरादून में बच्चों की यात्रा के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाकर शहर को बाल हितैषी बनाने के लिए चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट, देहरादून की आधारशिला भी रखी।
- देहरादून में 700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से जलापूर्ति, सड़क और जल निकासी से संबंधित परियोजनाओं का भी शिलान्यास ।
- प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप स्मार्ट आध्यात्मिक कस्बों के विकास और पर्यटन के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए श्री बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री-यमुनोत्री धाम में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की आधारशिला रखी गयी। साथ ही हरिद्वार में 500 करोड़ रु. से अधिक की लागत से नया चिकित्सा महाविद्यालय भी बनाया जाएगा।

सुरक्षित संपर्क वाली सात परियोजनाओं का उद्घाटन

- प्रधानमंत्री ने सात परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जिनमें क्षेत्र में गंभीर भूस्खलन की समस्या से निपटने के लिए यात्रा को सुरक्षित बनाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।
- चारधाम सड़क संपर्क परियोजना के तहत देवप्रयाग से श्रीकोट तक और एनएच-58 पर ब्रहमपुरी से कोडियाला तक सड़क चौड़ी करने की परियोजना का भी उद्घाटन किया।
- 1700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से यमुना नदी पर निर्मित 120 मेगावाट की व्यासी जलविद्युत परियोजना का भी उद्घाटन देहरादून में हिमालय संस्कृति केंद्र के साथ किया गया।
- हिमालयन संस्कृति केंद्र में एक राज्य स्तरीय संग्रहालय होगा, 800 सीट वाला कला सभागार, पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष, आदि जो लोगों को सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने के साथ-साथ राज्य की सांस्कृतिक विरासत की सराहना करने में मदद करेंगे।
- प्रधानमंत्री ने देहरादून में अत्याधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला (सुगंधित पौधों के लिए केंद्र) का भी उद्घाटन किया।

जो 2095 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा, जो श्रद्धालुओं के साथ-साथ आम जन जीवन को भी बेहद सुगम बनाएगा। इस कॉरिडोर का पहला सेक्शन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे से अक्षरधाम से शुरू होगा और बागपत के पास ईपीई जंक्शन पर समाप्त होगा। फिर 32 किमी. में से 18 किमी एलीवेटेड रोड जो शास्त्री पार्क, खजुरी खास और मंडोला से होकर गुजरेगा। ईपीई क्रासिंग के बाद यह 118 किमी ग्रीनफील्ड मार्ग होगा। हाइवे पर प्रवेश और निकास के लिए कुल 7 एक्जिट और 62 अंडरपास होंगे। निश्चित तौर से इस कॉरिडोर के निर्माण से आर्थिक व्यापारिक गतिविधि बढ़ेंगी और राष्ट्र की प्रगति के साथ-साथ उत्तराखंड के विकास को भी मिलेगी नई उड़ान। ●

हर घर टीके की दस्तक

तस्वीर... अलवर, राजस्थान में खेती कर रही महिलाओं की है। जहां हर घर दस्तक अभियान के तहत टीकाकरण किया गया।

कोविड जैसी सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचने का एक ही उपाय है, पूर्ण टीकाकरण। ऐसे समय जब कोविड ओमिक्रॉन समेत अलग-अलग वैरिएंट में हमारे सामने आ रहा है, और विशेषज्ञ बूस्टर डोज पर विचार कर रहे हैं, भारत अपने 55 फीसदी पात्र आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगा चुका है। इससे आगे बढ़कर अब केंद्र सरकार 'पूर्ण टीकाकरण लक्ष्य हमारा' संकल्प के साथ अपने देश के सभी नागरिकों का टीकाकरण करने के लिए 'हर घर दस्तक, हर घर टीका' अभियान चला रही है...

राजस्थान में अलवर जिला। यहां कृषक महिलाएं खेतों में काम कर रही थीं। ऐसे में उनका काम बाधित न हो और उनका टीकाकरण भी हो जाए इसके लिए स्वास्थ्यकर्मी खेत में गए और उन महिलाओं को वहीं कोविड का टीका दिया। इसी तरह, मध्य प्रदेश के घुघरी, मंडला में टीकाकरण अभियान के तहत कार्यस्थल पर ही लोगों का टीकाकरण किया गया ताकि, काम भी बाधित न हो और कोई भी व्यक्ति टीकाकरण अभियान से वंचित नहीं रहे। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। परिस्थितियां कैसी भी हो, ना रूकेंगे, ना थमेंगे लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते रहेंगे, के मूलमंत्र के साथ भारत में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई की व्यक्ति छूट ना जाए और सुरक्षा चक्र टूट ना जाए। इसके तहत केन्द्र सरकार ने 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक हर घर दस्तक अभियान चलाया जिसमें स्वास्थ्य कर्मी घर-घर से लेकर खेत-खलिहान गए ताकि देश में टीकाकरण से कोई भी वंचित नहीं रहे और 100

फीसदी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया जा सके। पूरे देश में अब तक 86 फीसदी से अधिक लोगों को कम से कम पहली डोज लगा दी गई है जो दुनिया के कई प्रमुख देशों में सर्वाधिक है। इतना ही नहीं, देश की 55 फीसदी से अधिक वयस्क आबादी को दोनों डोज दे दिए गए हैं। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। देश के जनसामान्य तक कोविड वैक्सीन की डिलिवरी सुनिश्चित करने के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। वर्तमान में मणिपुर, नागालैंड व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आईसीएमआर के 'आई-ड्रोन' का इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं 'भारत की जनता अगर एक बार कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं।' यही कारण है कि भारत की जनता और स्वास्थ्य कर्मियों की तत्परता की वजह से 15 दिसंबर तक भारत ने 138 करोड़ से अधिक वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है और 'सबके प्रयास' के मंत्र पर चलते हुए, स्वास्थ्य कर्मियों की कड़ी मेहनत से हिमाचल अपनी वयस्क आबादी को 100% दोनों डोज लगाने वाला पहला राज्य बन गया है।

खतरा टला नहीं, सावधानी जरूरी

भारत में चलाए जा रहे दुनिया के सबसे कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 138 करोड़ से अधिक वैक्सीन के डोज लगाए गए हैं। कोविड से बचाव के दो ही उपाय हैं। एक टीकाकरण, और दूसरा बचाव। हमें याद रखना होगा कि कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में टीकाकरण के साथ-साथ बचाव के उपाय भी करने चाहिए और मास्क का इस्तेमाल एवं कोविड उचित व्यवहार का अवश्य पालन करना चाहिए।

निगरानी बढ़ाएं- डब्ल्यूएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि कोविड का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 63 देशों में पहुंच चुका है और इसके संक्रमण की दर डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा है। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा कि अभी तक स्पष्ट नहीं है कि नया वेरिएंट इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। बीते महीने 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया था। इस बीच, भारत सरकार इस वेरिएंट पर लगातार नजर बनाए हुए है और निगरानी कर रही है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल का मानना है कि नए वेरिएंट का मतलब यह नहीं है कि चीजें बदतर होंगी, लेकिन निश्चित रूप से वे अनिश्चित होंगी। ऐसे में महामारी अभी भी आसपास है और हमें सावधान रहना चाहिए। साथ ही निगरानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करना चाहिए। ●

न्यू इंडिया का नया रिकार्ड

55%

से अधिक पात्र आबादी को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज दी गई।

86%

लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है।

138

करोड़ से डोज लगाई जा चुकी हैं देशभर में। यह दुनिया में सबसे ज्यादा।

100%

टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश।

वैक्सीन मैत्री- दुनिया के लिए भारत की संजीवनी

- भारत ने 20 जनवरी 2021 को वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत अन्य देशों को वैक्सीन डोज उपलब्ध कराना शुरु किया।
- 14 अक्टूबर 2021 को वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम एक बार फिर से शुरु किया गया। इसके तहत नेपाल, म्यांमार, ईरान और बांग्लादेश में से प्रत्येक को 10 लाख वैक्सीन डोज प्रदान किए गए। वर्तमान में 96 देशों को 'मेड इन इंडिया' का निर्यात किया जा रहा है।

> कोविड की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन का आंकड़ा पार कर लिया है और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वैरिएंट की खबरें भी हमें और भी सतर्क करती हैं, और सजग करती है। सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है।
>
> – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

घर-घर उजाला से जीवन हो रहा रोशन

किसी भी देश की प्रगति उसके पास उपलब्ध संसाधनों के सुनियोजित उपयोग और क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। भारत जैसे देश में कुल बिजली खपत का 20 फीसदी हिस्सा प्रकाश क्षेत्र के लिए उपयोग होता है। एक समय था जब इसमें एक बड़ा हिस्सा उन पुराने बल्बों का होता था, जो बिजली की अधिक खपत तो करते ही थे, साथ में अधिक खपत की वजह से जो अतिरिक्त स्रोतों से बिजली बनती थी, उसकी वजह से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता था। इसके विकल्प के रूप में एलईडी बल्ब बाजार में मौजूद तो था, पर महंगा होने की वजह से हर किसी की पहुंच इस तक नहीं थी। इसी के समाधान के लिए 5 जनवरी 2015 में शुरुआत हुई उजाला योजना की, जिसके जरिए अब तक मात्र 10 रुपये में करीब 37 करोड़ एलईडी बल्ब लोगों को दिए गए हैं, जिनसे रोशन हो रहे हैं देश के करोड़ों घर

तेलंगाना में सिकंदराबाद के एक अनाथालय में रहने वाली 15 साल की मर्सी सुसान बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। उसे पियानो बजाना और कराटे का अभ्यास करना बहुत पसंद है। वह अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रही है। गणित और विज्ञान उसके पसंदीदा विषय है। वह बताती हैं "पुराने के मुकाबले नए एलईडी में रोशनी ज्यादा होती है तो पढ़ने में भी आसानी होती है। पहले मैं पुराने बल्ब में 2 घंटे तक पढ़ाई कर पाती थी, लेकिन अब नए बल्ब में 4 घंटे पढ़ सकती हूं।" हरियाणा में सोनीपत से गुजरने वाले राजमार्ग पर ए1 ढाबे के पार्टनर देवदत्त शर्मा ने अपने ढाबे में ट्यूबलाइट की जगह एलईडी लाइट लगा लिया। इसके कारण उनका बिजली बिल छह महीने में ही 45 हजार रुपये से घटकर 15 हजार रुपये आ गया है। पूरी तरह से रोशन ढाबा पर अब ज्यादा ग्राहक आकर्षित होते हैं, सो अलग।" मर्सी और देवदत्त, दोनों ही उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें उजाला योजना के जरिए सस्ते एलईडी बल्ब हासिल हुए हैं।

5 जनवरी 2022 को 7 साल पूरे कर रही उजाला (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All (UJALA)) योजना विश्व की सबसे बड़ी घरेलू प्रकाश परियोजनाओं में से एक है। इतना ही नहीं, उजाला की वजह से भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा एलईडी बाजार बन गया है। 19 जुलाई को जहां सरकार द्वारा वितरित एलईडी की संख्या 13.3 करोड़ थी, वहीं 1 दिसंबर 2021 तक 177 फीसदी बढ़ोतरी के साथ यह 36.78 करोड़ हो गई। इस योजना का क्रियान्वयन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। उजाला योजना को एलईडी क्षेत्र में परिवर्तनकारी योगदान के लिये 'साउथ एशिया प्रोक्योरमेंट इनोवेशन अवार्ड' 2017, 'ग्लोबल सॉलिड स्टेट लाइटिंग' अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जैसे वैश्विक पुरस्कार दिये गए हैं।

प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना के रूप में नई शुरुआत

- प्रधानमंत्री ग्रामीण उजाला योजना के तहत भारत में दुनिया का सबसे सस्ता एलईडी बल्ब 10 रुपए में दिया जा रहा है। साथ ही इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 3 से 4 बल्ब दिए जा रहे हैं।
- इस योजना के तहत 15 से 20 करोड़ ग्रामीण परिवारों को बिना सब्सिडी वाली 60 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- बल्ब की कीमतें जहां 2014 में लगभग 310रु. थी वहीं आज घटकर 70 रुपए हो गई हैं।
- इस योजना के लिए केंद्र या फिर राज्य सरकार से कोई भी सब्सिडी नहीं ली जा रही है। इस योजना में जो भी खर्च आएगा वह एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) कर रही है। इस योजना की लागत की वसूली कार्बन ट्रेडिंग के माध्यम से की जाएगी।

वैश्विक पहचान

जीवन गुणवत्ता में सुधार - वार्षिक घरेलू बिलों में लगभग 15 फीसदी की कमी आई, उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में प्रति वर्ष 1600 करोड़ रुपये की बचत हुई।

उच्च गुणवत्ता का निर्माण - भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलईडी बाजार है, जो प्रति वर्ष 2140 करोड़ रुपये है।

जलवायु लक्ष्यों में योगदान - दुर्लभ ऊर्जा संसाधनों की बचत और भारत के कार्बन उत्सर्जन में प्रति वर्ष 3 बिलियन टन CO2 की कमी जो प्रति वर्ष 27 लाख कारों को सड़क से हटाने के बराबर है।

एलईडी से कम खपत होती है बिजली, होती है बचत

- यानि लाइट एमिटिंग डायोड के 7 वाट के बल्ब से 14 वाट के सीएफएल और 60 वाट के आईसीएल के बराबर रोशनी मिलती है।
- एलईडी बल्ब से आईसीएल की तुलना में लगभग 90 फीसदी और सीएफएल की तुलना में 50% ऊर्जा की बचत होती है।
- 140 घंटे तक इस्तेमाल करने पर एलईडी बल्ब 1 यूनिट बिजली की खपत करता है जबकि इतनी ही देर खपत करने पर सीएफएल में 2 यूनिट और आईसीएल में 9 यूनिट बिजली की खपत होती है।
- 140 घंटे तक इस्तेमाल करने पर एलईडी बल्ब में 4 रुपए की बिजली खर्च होती है जबकि इतनी ही देर खपत करने पर सीएफएल में 8 रुपए की बिजली खर्च होता है और आईसीएल में 36 रुपए की बिजली खपत होती है। ●

प्रगति में आई तेजी

बिजली की बचत

4800

करोड़ यूनिट से अधिक बिजली की बचत हुई हर साल उजाला योजना के जरिए।

19,110

करोड़ रुपया प्रति वर्ष लागत की बचत।

9,565

मेगावॉट से अधिक बिजली की मांग में कमी आई हर साल योजना की वजह से।

- 3,86,98,387 टन कार्बन डाई ऑक्साइड का प्रतिवर्ष उत्सर्जन कम हुआ। 1.10 करोड़ से अधिक स्ट्रीट लाइट लगाई गईं। 72 लाख से अधिक ट्यूबलाइट वितरित की गई। 23 लाख से अधिक पंखे वितरित किए गए।

> “
>
> देश को एक ऐसे समाधान की आवश्यकता थी जिसमें बिजली की खपत कम हो, रोशनी ज्यादा हो और लागत भी कम हो। इसी आवश्यकता ने उजाला योजना को जन्म दिया। एलईडी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। नीतियों में बदलाव किए गए। इससे बल्ब के कीमत में कमी आई और जैसे ही लोगों को इसके फायदों का पता चला, इसकी मांग भी बढ़ गई।
>
> – **नरेंद्र मोदी**, प्रधानमंत्री

जिन्होंने आजादी की जलाई अलख समाज के लिए छोड़ गए आदर्श

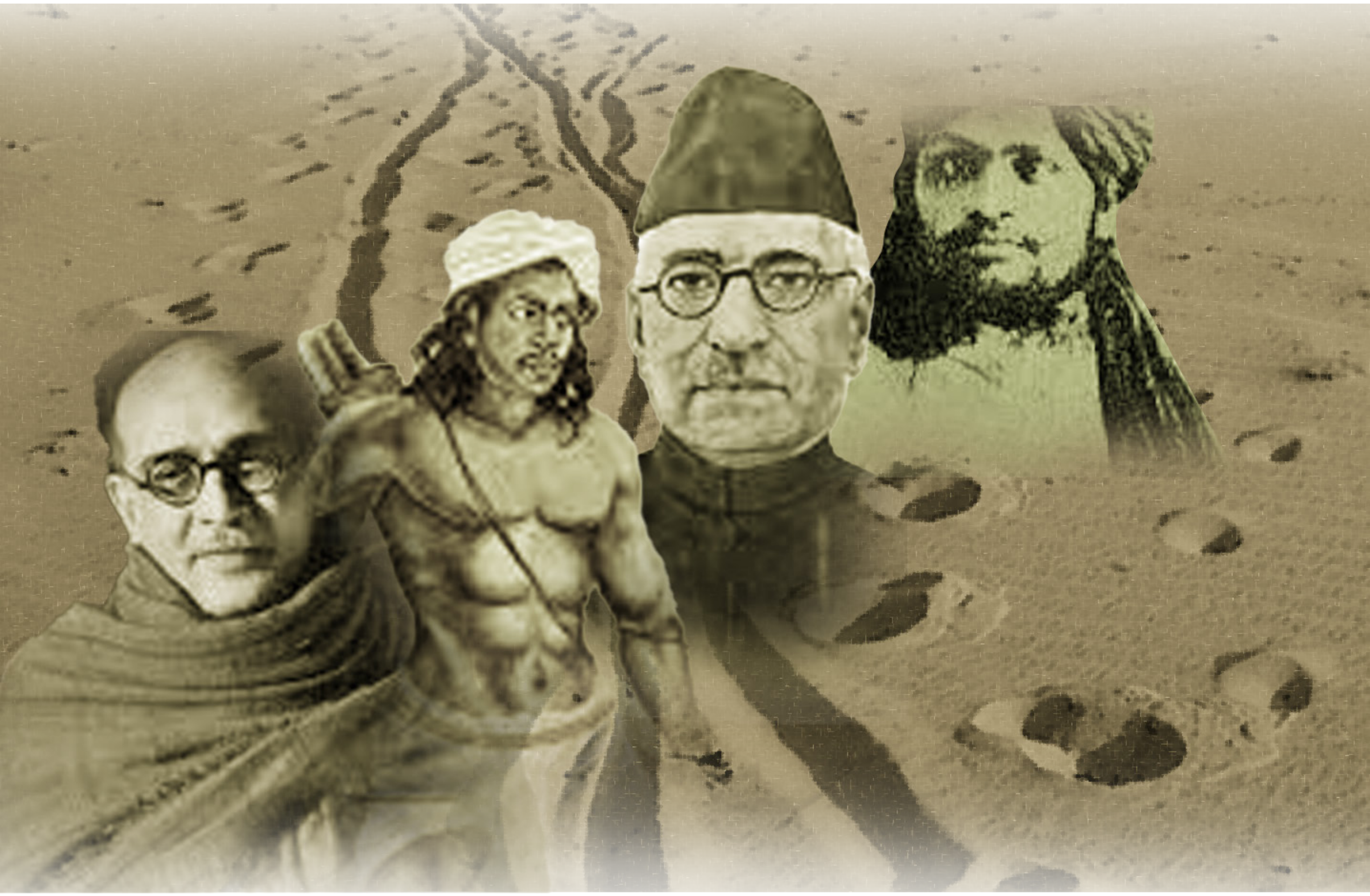

भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। इस संघर्ष में हर वर्ग और समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया और अपने-अपने तरीके से योगदान दिया। उनके संघर्षों का ही परिणाम है कि भारत 15 अगस्त 1947 में आजाद हो सका। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में इस बार महादेव भाई देसाई, तिलका मांझी, डॉ. सैफुद्दीन किचलू, विष्णु दामोदर चितले की कहानी, जिन्होंने ना केवल अंग्रेजों से लोहा लिया और बल्कि अपने पीछे एक ऐसा आदर्श भी छोड़ गए जो आज भी देशवासियों के लिए है अनुकरणीय...

महात्मा गांधी की परछाई बन स्वतंत्रता संग्राम में महादेव भाई देसाई ने निभाई महती भूमिका

जन्म - 1 जनवरी 1892 मृत्यु - 15 अगस्त 1942

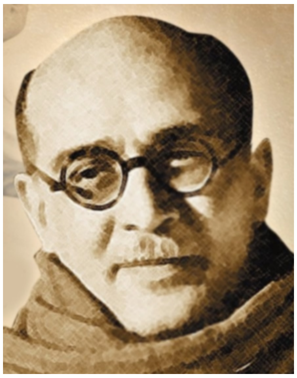

स्नातक तक की शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की और वकालत के पेशे से भी जुड़े।

महादेव भाई देसाई कहने को तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निजी सचिव थे, लेकिन उन दोनों के बीच उम्र में करीब 24 साल का अंतर था। उम्र में इतना अंतर होने के बावजूद दोनों के बीच का संबंध बहुत सहज और मधुर था। यही कारण है कि महादेव देसाई को लोग महात्मा गांधी की परछाई कहते थे।

इतना नहीं, कुछ लोग उन्हें गांधी का दाहिना हाथ मानते थे, जो बापू की सभी जरूरतों का ध्यान रखते थे। माना जाता है कि वह महात्मा गांधी के टाइपिस्ट, अनुवादक, काउंसलर, कूरियर, दुभाषिया, संकटमोचक सहित और भी बहुत कुछ थे। यहां तक कि वह रसोइये भी थे और उनके हाथ की बनी खिचड़ी की गांधी खासतौर से तारीफ करते थे। देसाई से स्नेह के कारण ही महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा उन्हें अपने पुत्र जैसा मानते थे। महात्मा गांधी ने 1917 में देसाई से हुई अपनी पहली ही मुलाकात में उन में छिपी हुई विशेषताओं को पहचान लिया और उनसे अपने साथ काम करने का आग्रह किया था। ऐसे में महात्मा गांधी का 1917 में देसाई से जो संबंध बना वह 15 अगस्त 1942 तक देसाई की अंतिम सांस तक जारी रहा। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के अपने ऐतिहासिक भाषण में 'करो या मरो' का नारा दिया था। 9 अगस्त की सुबह ही अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, महादेव देसाई आदि को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खां महल में बंद कर दिया। इसी जेल में 15 अगस्त को महादेव देसाई का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उन्होंने 50 साल की जिंदगी में ही 100 साल का काम कर दिया। महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार आगा खां के महल में ही उनकी समाधि बनवाई गई। एक साल के बाद जब कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ तो उनकी समाधि भी महादेव देसाई की समाधि के निकट ही बनवाई गई। सूरत के एक गांव में 1 जनवरी 1892 को जन्मे महादेव देसाई ने महात्मा गांधी की गुजराती में लिखी आत्मकथा 'सत्य के प्रयोग' का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वह लंबे समय तक डायरी लेखन करते रहे और इस डायरी में महात्मा गांधी की जीवनशैली, उनके क्रियाकलापों आदि का विस्तृत विवरण मिलता है। गांधी के चरित्र, विचार और उनके दर्शन को समझने के लिए यह डायरी आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

हांसी, हांसी चढ़ गो फांसी... गीत की प्रेरणा बन गए थे तिलका मांझी

जन्म: 11 फरवरी 1750, शहीदी दिवस : 13 जनवरी 1785

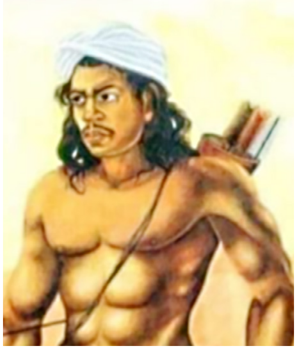

दरअसल पहाड़िया भाषा में 'तिलका' का अर्थ है गुस्सैल और लाल-लाल आंखों वाला व्यक्ति।

एक युवक 13 जनवरी 1784 को ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही घोड़े पर सवार अंग्रेज सुप्रींटेंडेंट क्लीवलैंड उस ओर आया उसे अपने जहरीले तीर से मार गिराया। ऐसा करने वाला यह युवक कोई और नहीं, बल्कि तिलका मांझी था। मांझी ने अंग्रेजों के खिलाफ उस समय लड़ाई शुरु की थी, जब कहीं कोई विद्रोह की बात भी नहीं हो रही थी। इस घटना के बाद अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए। एक रात तिलका मांझी और उनके क्रांतिकारी साथी पारंपरिक उत्सव मना रहे थे तभी अचानक उन पर हमला कर दिया गया। मांझी, अचानक हुए इस हमले में तो बच निकले, लेकिन इस हमले में कई और लोग मारे गए। 13 जनवरी 1785 को एक अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में तिलका मांझी को बंदी बना लिया गया और उन्हें घोड़े से बांध कर कई मील घसीट कर भागलपुर लाया गया। अंग्रेज

सहित सभी लोग आश्यर्चचकित थे कि मीलों घसीटे जाने के बावजूद तिलका मांझी जीवित कैसे रह गए। हालांकि, अंग्रेजी हुकूमत कहां मानने वाली थी। उन्होंने मांझी को भागलपुर के चौराहे पर एक विशाल वटवृक्ष पेड़ से लटका कर फांसी दे दी। वह महान देशभक्त देश की खातिर हंसते-हंसते फांसी से लटक गया। बाद में आजादी के लड़ाकों ने तिलका मांझी का अनुसरण करते हुए 'हांसी, हांसी, चढ़ गो फांसी' गीत गाए। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाने वाले तिलका मांझी, दरअसल पहाड़िया समुदाय के एक ऐसे वीर सिपाही थे जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद माना जाता है। 11 फरवरी 1750 को बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में एक संथाल परिवार में जन्मे तिलका मांझी का असल नाम जबरा पहाड़िया बताया जाता है। उनका तिलका नाम पड़ने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। कहते हैं कि तिलका नाम उन्हें अंग्रेजों ने दिया था। एक बार एक अंग्रेज ने इनकी घूरती लाल आंखों में देखा था, जिसके बाद उन्हें तिलका नाम दे दिया गया। दरअसल पहाड़िया भाषा में 'तिलका' का अर्थ है गुस्सैल और लाल-लाल आंखों वाला व्यक्ति होता है। अंग्रेजों के खिलाफ 1771 से लेकर 1784 तक करीब 13 साल अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभालने वाले तिलका मांझी ने स्थानीय महाजनों और सामंतों की नींद को भी उड़ाए रखा। संथालों द्वारा किए गए प्रसिद्ध संथाल विद्रोह का नेतृत्व भी तिलका मांझी ने ही किया था। तिलका मांझी के नाम पर भागलपुर में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय है। साथ ही बांग्ला की सुप्रसिद्ध लेखिका महाश्वेता देवी ने तिलका मांझी के जीवन और विद्रोह पर बांग्ला भाषा में एक उपन्यास 'शालगिरर डाके' की रचना की है, जिसे हिंदी में 'शालगिरह की पुकार पर' नाम से प्रकाशित किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की अहमियत का पता इस बात से चलता है कि उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हुए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाना शुरु किया है।

अलग पाकिस्तान की मांग का विरोध करने वाले राष्ट्रवादी थे डॉ. किचलू

जन्मः 15 जनवरी 1888, मृत्यु : 9 अक्टूबर 1963

15 जनवरी 1888 को अमृतसर में जन्मे डॉ. सैफुद्दीन किचलू ने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी से स्नातक और जर्मन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की थी।

अमृतसर के जलियांवाला बाग का नाम भला किसने नहीं सुना होगा। यह वही जगह है जहां अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर के नेतृत्व में वहां जमा सैकड़ों लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। माना जाता है कि इस हमले 1,000 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। जलियांवाला बाग में उस दिन जो भीड़ जमा हुई थी वह किसी और के लिए नहीं बल्कि अन्य मुद्दों के साथ-साथ लोकप्रिय नेता डॉ. सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्र हुई थी, जिन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। जब अंग्रेजी हुकूमत ने 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया तो पेशे से वकील और हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्षधर डॉ. किचलू ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जबर्दस्त आवाज उठाई थी। दरअसल, इस कानून के जरिए सरकार बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी। देश भर में इस कानून का विरोध होने लगा। ऐसे में किचलू ने लोगों से हड़ताल और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अहिंसक सत्याग्रह में भाग लेने का आग्रह किया। यह किचलू की अपील का ही असर था कि 30 मार्च 1919 को उनकी सार्वजनिक सभा में लगभग 30,000 लोग शामिल हुए, जहां उन्होंने दमदार भाषण दिया। इसके बाद डॉ. किचलू और डॉ. सत्यपाल ने 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर में सरकार- विरोधी एक जुलूस का नेतृत्व किया जिसके बाद इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और धर्मशाला में नजरबंद कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लगातार सक्रिय रहने वाले किचलू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में खुल कर भाग लिया था। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की अलग पकिस्तान की मांग का डटकर विरोध किया था और 1947 में देश के बंटवारे के खिलाफ भी खुलकर अपने विचार रखे थे। वह दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापकों में से एक थे। माना जाता है कि उन्होंने ही भगत सिंह द्वारा स्थापित नौजवान भारत सभा के पीछे मार्गदर्शक की भूमिका भी निभाई थी। स्वतंत्रता के बाद, किचलू ने शांति की बहाली और सोवियत-भारत संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए काम करना जारी रखा। वे 1952 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हाल ही में जलियांवाला बाग में स्मारक के जीर्णोद्धार और उन्नयन का काम किया गया है। साथ ही स्मारक स्थल पर संग्रहालय, गैलरी और ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी की स्थापना की गई है।

आजादी के आंदोलन के लिए अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में खड़े हुए थे विष्णु दामोदर

जन्म : 4 जनवरी 1906, मृत्यु- 1961

बचपन से ही अडिग इरादे और धुन के पक्के विष्णु दामोदर चितले का जन्म 4 जनवरी 1906 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। प्रसिद्ध कम्युनिस्ट होने के बावजूद वह एक राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। आजादी की लड़ाई के साथ-साथ वह किसान और मजदूरों के हित के लिए काम करते रहे और महात्मा गांधी की अगुवाई में चलाए गए नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया। भाई चितले के नाम से जाने जाने वाले विष्णु दामोदर चितले ने 1929 में पुणे से बी.ए. की परीक्षा पास की। हालांकि, भारत को आजाद कराने के लिए चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन में रूचि होने के कारण वह एम.ए. और कानून की परीक्षा पास नहीं कर सके। विष्णु दामोदर चितले एक ऐसे निडर व्यक्ति थे जो मार्क्सवादी साहित्य से प्रभावित और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होने के बावजूद कभी भी पार्टी की नीति का अंधा अनुकरण नहीं किया। जब उनको कम्युनिस्ट पार्टी की नीति भारत के राष्ट्र हितों के विपरीत दिखाई दी तो उन्होंने खुलकर निडरता के साथ इसका विरोध किया। माना जाता है कि जब कम्युनिस्टों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था तब भाई चितले ने उसका समर्थन किया था। इससे उनकी पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा गया था लेकिन उनकी कुशलता के कारण ही 1951 में उन्हें पार्टी में फिर से वापस ले लिया गया। चीन के भारत पर आक्रमण के समय वैचारिक रूप से उनका फिर कम्युनिस्टों से मतभेद हो गया था और उन्होंने भारत के पक्ष का समर्थन किया था। इतना ही नहीं भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के साथ-साथ वे गोवा मुक्ति आंदोलन में भी सक्रिय रहे। उस समय वह पुर्तगालियों की गोलियों की परवाह न करके 1000 व्यक्तियों को लेकर गोवा की सीमा पर पहुंच गए थे। ●

विष्णु दामोदर चितले एक ऐसे निडर व्यक्ति थे जो मार्क्सवादी साहित्य से प्रभावित और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य होने के बावजद कभी भी पार्टी की नीति का अंधा अनुकरण नहीं किया।

आजादी के अमृत महोत्सव की देश भर में गूंज

- कौशल विकास, उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 29 नवंबर, को सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम 'आजादी का डिजिटल महोत्सव' का शुभारंभ किया। इसका प्रत्येक दिन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक लक्ष्य को समर्पित रहा।
- संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 4 दिसंबर को स्वच्छ भारत लोगो के लिए आजादी का डिजिटल महोत्सव के दौरान अनंत गोपाल खसबरदार को सम्मानित किया। उन्होंने '100 करोड़ टीकाकरण लोगो' के लिए यासीन हारून सुदेसरा, 'लोकपाल' के लिए प्रशांत मिश्रा, 'बांस मिशन लोगो' के लिए साई राम गौड़ एदिजी की सराहना की।
- भारत सरकार ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के प्रमुख समारोह के हिस्से के रूप में 6 दिसंबर, 2021 को महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन किया।
- आजादी के 75 वर्ष का जश्न मनाने के लिए, आरईसी लिमिटेड ने असम के कामरूप जिले के सोनापुर और आस-पास के गांवों में 'बिजली उत्सव' का आयोजन किया।
- बीआरओ मोटरसाइकिल अभियान **India@**75 राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र निर्माण और सड़क सुरक्षा जागरूकता यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 अक्टूबर को रवाना किया था।
- आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी समुदायों ने आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान आदिवासी लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को बड़े उत्साह के साथ मनाया।
- आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के सप्ताह समारोह में दक्षिणी राज्यों के 86 आदिवासी उद्यमियों को सम्मानित किया।
- आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्र ने वाराणसी में महिलाओं को पोषण और फोर्टिफाइड चावल के बारे में जागरूक किया।
- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
- आजादी का अमृत महोत्सव के तहत पंचायती राज मंत्रालय ने जनजातीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के सहयोग से विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

भारत-रूस संबंधों को मिला नया आयाम

आजादी के बाद से ही जब भारत बाकी दुनिया के साथ कदमताल की कोशिश कर रहा था, रूस के रूप में उसे अनन्य सहयोगी मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्वकाल में यह दोस्ती और प्रगाढ़ हुई है। रूस और भारत के रिश्ते इस दौर में किस मुकाम पर हैं, इसे 6 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक दिन की भारत यात्रा से भी समझ सकते हैं, क्योंकि बीते दो वर्षों में कोविड की विपरीत परिस्थितियों के बीच पुतिन का यह सिर्फ दूसरा विदेश दौरा है

दिल्ली में 6 दिसंबर को जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौर में दोनों देशों की दोस्ती को कैसे एक नया आयाम दिया, यह पूरी दुनिया ने देखा। पुतिन जी-20 समिट के लिए रोम नहीं गए थे। वो ग्लासगो में पर्यावरण और जलवायु पर हुए कॉप-26 सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे। हाल ही में उन्हें चीन का दौरा भी करना था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था लेकिन पुतिन वहां भी नहीं गए, लेकिन 21वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन में आकर उन्होंने अहम संदेश दिया और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात में कहा, "पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई मौलिक बदलाव आए हैं । कई तरह के भू-राजनैतिक समीकरण उभरे हैं। किन्तु इन सभी के बीच भारत -रूस मित्रता निरंतर स्थिर रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ सहयोग किया है, एक दूसरे की संवेदनशीलता का भी विशेष ध्यान रखा है। यह सचमुच अंतरराष्ट्रीय दोस्ती का एक अद्वितीय और विश्वस्त मॉडल है।"

28 समझौतों पर लगी मुहर

- दोनों देश 2025 तक दो-तरफा निवेश को 50 अरब डॉलर और व्यापार को 30 अरब डॉलर के पार ले जाना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा में 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।
- दोनों देशों ने कनेक्टिविटी से लेकर सैन्य सहयोग, ऊर्जा साझेदारी से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र में भागीदारी के अनेक मुद्दे शामिल हैं। साथ ही संयुक्त बयान जारी कर अपनी दोस्ती को शांति, प्रगति और समृद्धि की साझेदारी करार दिया।
- रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ और रक्षा मंत्री सर्गेई शोउगू के साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की 2+2 बातचीत भी हुई।
- विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बैठक के बाद कहा, 'इस यात्रा में 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए है। समझौतों में व्यापार, ऊर्जा, बौद्धिक संपदा, बैंकिंग, अकाउंटेंसी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। वार्ता में बाइलेट्रल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पर फोकस रहा।'
- एक तरफ जहां अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की योजना आगे बढ़ाने पर रजामंदी हुई। वहीं, दोनों पक्ष जल्दी ही भारत के चेन्नई को रूस के व्लादिवोस्तक तक जोड़ने वाले समुद्री गलियारे पर भी तेजी से काम करने को सहमत हैं।
- भारत और रूस ने अपने सैन्य और तकनीकी सहयोग समझौते को अगले 10 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. इसके तहत साझा सैन्य उत्पादन और अनुसंधान-विकास पर सहमति बनी है। भारत के रिजर्व बैंक और रूस के बैंक ऑफ रशिया ने सायबर हमलों के खिलाफ मिलकर लड़ने का करार किया
- दोनों देशों ने इस बारे में भी सहमति जताई कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। संयुक्त बयान में दोनों देशों ने अलकायदा, आईएसआईएस और लश्कर-ए-तोयबा जैसे संगठनों के खिलाफ एकजुट कार्रवाई करने का भी संकल्प जताया ।●

प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए QR कोड स्कैन करें।

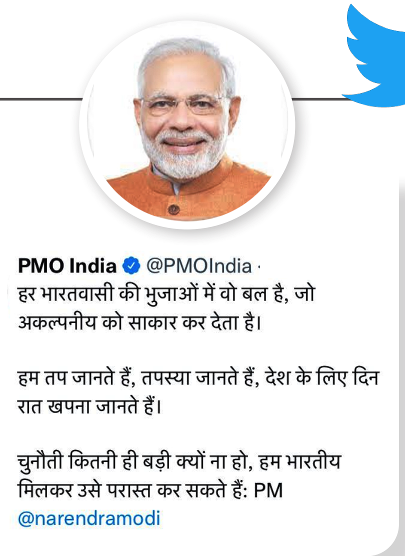

PMO India @PMOIndia ·

हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, जो अकल्पनीय को साकार कर देता है।

हम तप जानते हैं, तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं।

चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं: PM @narendramodi

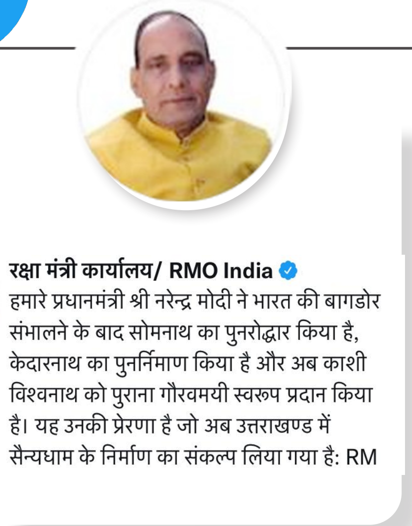

रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की बागडोर संभालने के बाद सोमनाथ का पुनरोद्धार किया है, केदारनाथ का पुनर्निमाण किया है और अब काशी विश्वनाथ को पुराना गौरवमयी स्वरूप प्रदान किया है। यह उनकी प्रेरणा है जो अब उत्तराखण्ड में सैन्यधाम के निर्माण का संकल्प लिया गया है: RM

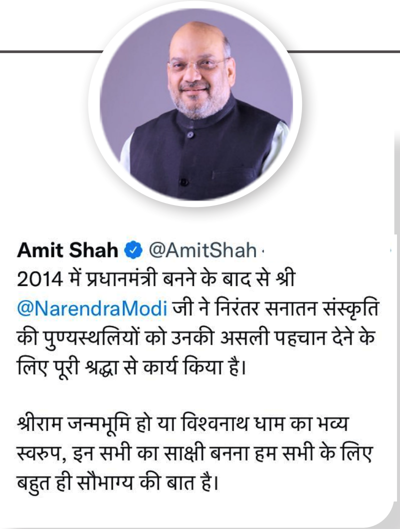

Amit Shah @AmitShah ·

2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से श्री @NarendraModi जी ने निरंतर सनातन संस्कृति की पुण्यस्थलियों को उनकी असली पहचान देने के लिए पूरी श्रद्धा से कार्य किया है।

श्रीराम जन्मभूमि हो या विश्वनाथ धाम का भव्य स्वरुप, इन सभी का साक्षी बनना हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है।

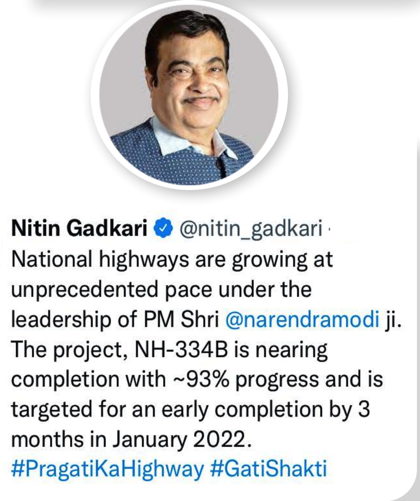

Nitin Gadkari @nitin_gadkari ·

National highways are growing at unprecedented pace under the leadership of PM Shri @narendramodi ji. The project, NH-334B is nearing completion with ~93% progress and is targeted for an early completion by 3 months in January 2022. #PragatiKaHighway #GatiShakti

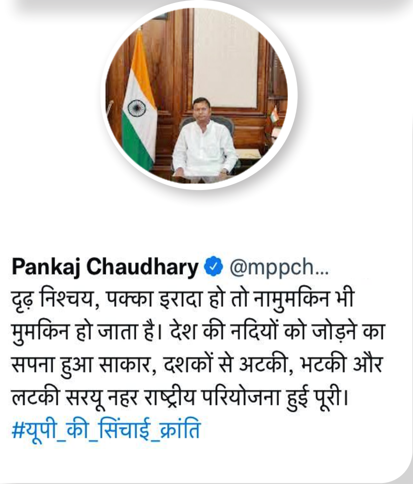

Pankaj Chaudhary @mppch...

दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। देश की नदियों को जोड़ने का सपना हुआ साकार, दशकों से अटकी, भटकी और लटकी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हुई पूरी। #यूपी_की_सिंचाई_क्रांति

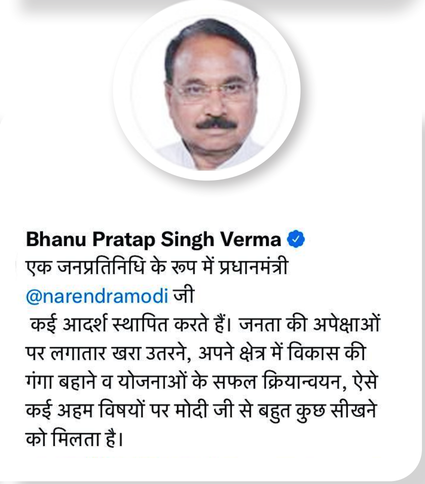

Bhanu Pratap Singh Verma

एक जनप्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री @narendramodi जी

कई आदर्श स्थापित करते हैं। जनता की अपेक्षाओं पर लगातार खरा उतरने, अपने क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने व योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, ऐसे कई अहम विषयों पर मोदी जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।

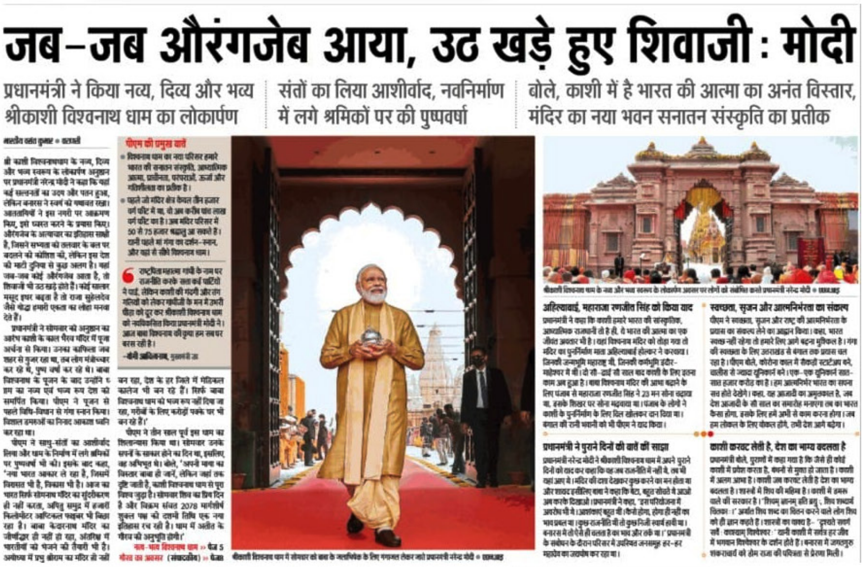

जब-जब औरंगजेब आया, उठ खड़े हुए शिवाजी : मोदी

प्रधानमंत्री ने किया नव्य, दिव्य और भव्य श्रीकाशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण

संतों का लिया आशीर्वाद, नवनिर्माण में लगे श्रमिकों पर की पुष्पवर्षा

बोले, काशी में है भारत की आत्मा का अनंत विस्तार, मंदिर का नया भवन सनातन संस्कृति का प्रतीक

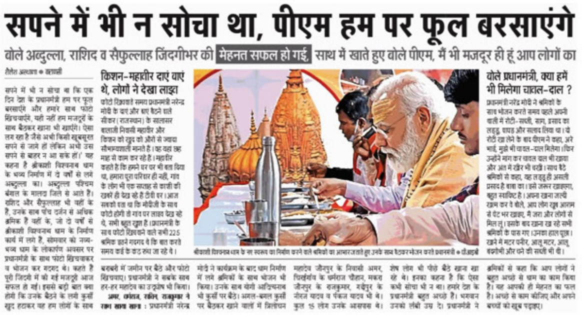

सपने में भी न सोचा था, पीएम हम पर फूल बरसाएंगे

बोले अब्दुल्ला, राशिद व सैफुल्लाह जिंदगीभर की मेहनत सफल हो गई, साथ में खाते हुए बोले पीएम, मैं भी मजदूर ही हूं आप लोगों का

किशन-महावीर दाएं बाएं थे, लोगों ने देखा लाइव

बोले प्रधानमंत्री, क्या हमें भी मिलेगा चावल-दाल ?

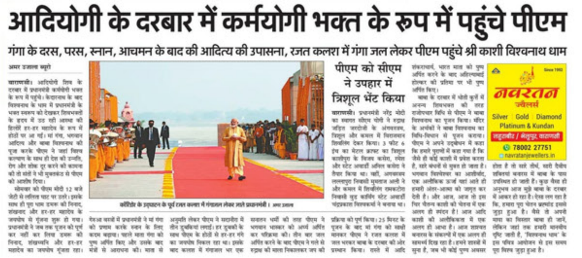

आदियोगी के दरबार में कर्मयोगी भक्त के रूप में पहुंचे पीएम

गंगा के दरस, परस, स्नान, आचमन के बाद की आदित्य की उपासना, रजत कलश में गंगा जल लेकर पीएम पहुंचे श्री काशी विश्वनाथ धाम

पीएम को सीएम ने उपहार में त्रिशूल भेंट किया

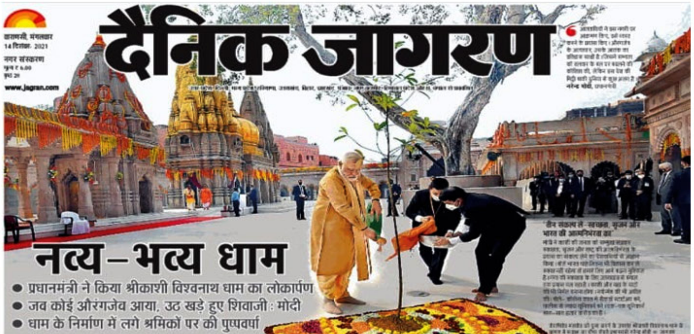

दैनिक जागरण

वाराणसी, मंगलवार 14 दिसंबर 2021

www.jagran.com

नव्य-भव्य धाम

- प्रधानमंत्री ने किया श्रीकाशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण
- जब कोई औरंगजेब आया, उठ खड़े हुए शिवाजी : मोदी
- धाम के निर्माण में लगे श्रमिकों पर की पुष्पवर्षा

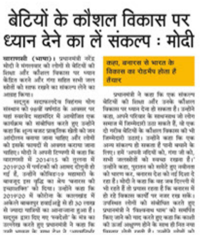

बेटियों के कौशल विकास पर ध्यान देने का लें संकल्प : मोदी

कहा, बनारस से भारत के विकास का रोडमैप होता है तैयार

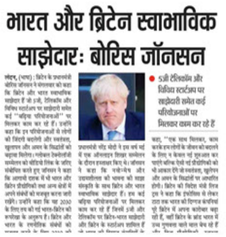

भारत और ब्रिटेन स्वाभाविक साझेदार: बोरिस जॉनसन

5जी टेलिकॉम और विविध स्टार्टअप पर साझेदारी समेत कई परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं

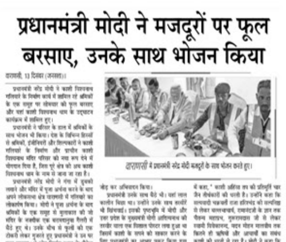

प्रधानमंत्री मोदी ने मजदूरों पर फूल बरसाए, उनके साथ भोजन किया

वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजदूरों के साथ भोजन करते हुए।

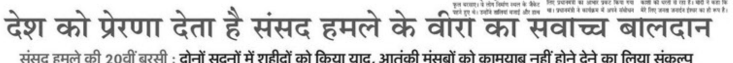

देश को प्रेरणा देता है संसद हमले के वीरों का सर्वोच्च बलिदान

संसद हमले की 20वीं बरसी : दोनों सदनों में शहीदों को किया याद, आतंकी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देने का लिया संकल्प

आर.एन.आई
DELHIN/2020/78812
1-15 जनवरी, 2022

न्यू इंडिया
समाचार
पाक्षिक

आरएनआई DELHIN/2020/78812, दिल्ली पोस्टल लाइसेंस नंबर -
DL (S)-1/3550/2020-22 डब्ल्यूपीपी संख्या U (S)-98/2020-22, posting at BPC,
Meghdoot Bhawan, New Delhi - 110 001 on 26-30 advance Fortnightly
(प्रकाशन तिथि - 21 दिसंबर 2021, कुल पृष्ठ-48)

12 जनवरी

राष्ट्रीय युवा दिवस

स्वामी विवेकानंद जयंती

> "स्वामी विवेकानंद ने भारत को एक ऐसी सांस्कृतिक चेतना के रूप में देखा, जो सदियों से चली आ रही है और सांस ले रही है, एक ऐसा भारत जो विपरीत भविष्यवाणियों के बावजूद हर चुनौती के बाद मजबूत होता है। वह भारत को 'प्रबुद्ध' बनाना चाहते थे या जागृत करना चाहते थे।"

—नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री

संपादक:
जयदीप भटनागर, प्रधान महानिदेशक,
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक और मुद्रक:
सत्येन्द्र प्रकाश, प्रधान महानिदेशक, बीओसी
(ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन)

कमरा संख्या- 278, द्वितीय तल,
ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन,
सूचना भवन, द्वितीय तल, नई दिल्ली-
110003 से प्रकाशित

मुद्रण: जेके ऑफसेट ग्राफिक्स प्राइवेट
लिमिटेड, बी-278, ओखला इंडस्ट्रियल
एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020